लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं]
[Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूचि/CONTENTS

अंक 37—सोमवार, 11 अप्रैल, 1966/21 चैत्र, 1888 (शक)

*No.*37,— *Monday, April* 11, 1966/*Chaitra* 21, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

***ता० प्र० संख्या**

*S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1040	प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों सम्बन्धी जानकारी	Information Re. Physiographic Regions	6379–81
1041	अनिवार्य राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण	Compulsory N.C.C. Training .	6381–83
1042	नागा विद्रोहियों में गतिविधियां	Activities of Hostile Nagas . .	6384–88
1043	फिजी में संवैधानिक परिवर्तन	Constitutional Changes in Fiji .	6388–89
1044	थुम्बा राकेट परीक्षण	Thumba Rocket Experiment .	6390–91
1045	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों के लिये भूमि	Land for families of Soldiers who had died in Indo-Pak. conflict .	6391–93
1046	कृषि विकास के लिये प्रचार योजनायें	Propaganda Schemes for Agricultural Development . .	6393–94

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1047	ईशापुर के आयुध कारखानों के कर्मचारी	Workers in Ordnance Factories at Ichapore	6395
1048	कलकत्ता में नेताजी की मूर्ति के उद्घाटन समारोह का प्रसारण	Broadcast of Unveiling Ceremony of Netaji's Statue in Calcutta .	6395
1049	जम्बिया में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugee in Zambia	6395–96
1050	एशियाई नेताओं का सम्मेलन	Conference of Asian Leaders .	6396
1051	आकाशवाणी द्वारा चुनाव सम्बन्धी प्रचार	Election Propaganda by A.I.R. .	6396
1052	भारत में बनाये गये हथियारों तथा गोलाबारूद की मांग	Demand for India-made Arms and Ammunition	6396–97
1053	बोरझार में वायु सेना के विमान की दुर्घटना	Air Force Crash at Borjhar .	6397
1054	बर्मा में मिजो आदिम जाति लोगों की गिरफ्तारी	Arrest of Mizo Tribesmen in Burma	6397

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on floor of the House by that Member.

1—53 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1055	सेना में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Army . .	6397–98
1056	नये सैनिक स्कूल	New Sainik Schools . . .	6398
1057	छिपे हुए नागाओं का कोहिमा के निकट मुख्यालय	Underground Nagas Headquarters near Kohima . .	6398
1058	विविध भारती से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापन	Commercial Advertising in Vividh Bharati	6398–99
1059	पाकिस्तान के लिये चीन के टैंक	Chinese Tanks for Pakistan . .	6399
1060	विद्रोही नागाओं और मिजो लोगों की गतिविधियां	Activities of Hostile Nagas and Mizos	6399
1061	पश्चिम जर्मनी की सरकार के प्रतिनिधियों से पत्र	Note from West German Governments' Representatives . .	6399
1062	कीनिया में भारतीय	Indians in Kenya . .	6400
1063	जापान के प्रधान मंत्री का भाषण	Speech of the Japanese Prime Minister	6400
1064	बर्मा में भूमि का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Land in Burma	6400–01
1065	सिक्किम तथा तिब्बत से आये हुए शरणार्थियों को बसाया जाना	Rehabilitation of Refugees from Sikkim and Tibet . . .	6401
1066	सामान्य निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण	Broadcasts by Political Parties during General Elections .	6401
1067	भारत द्वारा क्षेत्र खाली न किये जाने के बारे में पाकिस्तान का आरोप	Pakistan's allegation re. Areas not vacated by India . . .	6401–02
1068	पेकिंग में भारतीय कार्यवाहक राजदूत का स्वागत समारोह से उठकर चले जाना	Walk-out by Indian Charge d' Affairs in Peking . . .	6402
1069	पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो का भाषण	Speech of Mr. Z. A. Bhutto, Pakistan Foreign Minister . .	6402–03

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3492	आसाम में राष्ट्रीय छात्रसेना दल की राज्य सलाहकार समिति	State Advisory Committee of N.C.C. in Assam . . .	6403
3493	राजस्थान के सैनिकों को वीरता पुरस्कार	Gallantry Awards to Military personnel from Rajasthan . .	6403–04
3494	स्थल सेना के एक अधिकारी का आवश्यक कागजात छोड़ कर भाग जाना	Important Papers left behind by an Army Officer . . .	6404
3495	लाहोर और सियालकोट पर कब्जा करने की योजना	Plan to capture Lahore and Sialikot	6045

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3496	राजस्थान और कच्छ में हवाई अड्डे	Aerodromes in Rajasthan and Kutch	6405
3497	पूर्वी पाकिस्तान राइफल द्वारा गोली बारी	Firing by East Pakistan Rifles	6405
3498	तिब्बति शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees	6406
3499	मद्रास में अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Plant at Madras	6406
3500	भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं	I.A.F. Accidents	6406
3501	कीनियां में भारतीय लोग	Indians in Kenya	6406–07
3502	काश्मीर में टेलीविजन कार्यक्रम	Television Programme in Kashmir	6407
3503	पटना आकाशवाणी केन्द्र में शक्तिशाली ट्रान्समिटर का लगाया जाना	Powerful Transmitter at Patna Radio Station	6407
3504	तिब्बति शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees	6407–08
3505	आयुध कारखाना, किर्की में विस्फोट	Explosion in Ordnance Factory, Kirkee	6408
3506	भारत में पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Pak. Prisoners-of-war in India	640
3507	अन्तर्राष्ट्रीय कानून-संहिता	Code of International Law	6408–09
3508	बड़ोदा में सनिक बैरकों में विस्फोट	Explosion in Military Barracks at Baroda	6409
3509	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में पुस्तकालय	Library in Indian Embassy in Nepal	6409–10
3510	इस्तम्बूल, दमिश्क और वेनटियान स्थित भारतीय दूतावासों में पुस्तकालय	Libraries in Indian Missions at Instanbul, Damascus and Vientiane	6410
3511	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के पुस्तकालय	Libraries of Indian Missions Abroad	6410–11
3512	बेरूत, अदिस अबाबा, काहिरा, आदि स्थानों में स्थित भारतीय दुतावासों के पुस्तकालय	Libraries of Indian Embassies in Beirut, Addis Ababa, Cairo etc.	6411
3513	भारत 1965 डायरियां (दैनन्दिनियां)	India 1965 Diaries	6411–12
3514	प्रधान सूचना अधिकारी	Principal Information Officer	6412
3515	स्थल सेना में चुने हुए लोगों की अनिवार्य भर्ती	Selective Conscription in the Army	6412
3516	अदन भारतीय आयुक्त का निवास स्थान	Residence of Indian Commissioner in Aden	6413
3517	एक भारतीय दुतावास तथा एक राजदूत के निवास स्थान के लिये फर्नीचर	Furniture for an Indian Embassy and Residence of an Ambassador	6413–14
3518	आर्म्मी आर्डनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क	L.D.Cs. in Ordnance Corps	6414

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3519	संसद सदस्यों तथा विधान सभा-सदस्यों को जीपों का बेचा जाना	Sale of Jeeps to M.Ps and M.L.As	6414
3520	मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Stations in Mysore . .	6414
3521	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोग	Ex-I.N.A. Personnel . . .	6415
3522	मद्रास में अणु संयंत्र	Atomic Plant at Madras . .	6415
3523	उड़ीसा में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के केडेंट	N.C.C. Cadets in Orissa . .	6416
3524	कामटी में राष्ट्रीय छात्रसेना दल का प्रशिक्षण	N.C.C. Training at Kamtee .	6416
3525	जर्मन लोक-तंत्रात्मक गणराज्य से प्रतिनिधि मंडल	Delegation from German Democratic Republic . . .	6417
3526	जवानों के लिये भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Servicemen	6417
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	प्रादेशिक खाद्य निदेशालय में नियोजीत कर्मचारियों की छंटनी	Reported Retrenchment of Workers employed under Regional Food Directorate.	6417–18
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table.	6418
अनुदानों की मांगें—		Demands for Grants—	
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—	Ministry of Petroleum and Chemicals—	
	श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	6418–19
	श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray . .	6419–20
	श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	6420–21
	श्री टे० सुब्रह्मण्यम	Shri T. Subramanyam .	6421
	श्री राम बरुआ	Shri R. Barua . . .	6421–22
	श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan . .	6422–23
	श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Verma .	6423–24
	श्री इक्बाल सिंह	Shri Iqbal Singh . .	6424–26
	श्री राजाराम	Shri Rajaram . . .	6426
	श्री दलजीत सिंह	Shri Daljit Singh . .	6426–27
	श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	6427–28
	श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	6428
	डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh .	6428–29
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty	6429
	श्री अलगेसन	Shri Alagesan . . .	6429–34
	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय—	Ministry of Irrigation and Power—	
	श्री नरसिम्हा रेड्डी	Shri Narasimha Reddy .	6435–36
	श्री बृजराज सिंह-कोटा	Shri Brij Raj Singh-Kotah .	6437–38
	श्रीमती विमला देवी	Shrimati Vimla Devi . .	6438–40

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 11 अप्रैल, 1966/21 चैत्र, 1888 (शक)
Monday, April 11, 1966/Chaitra 21, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों संबंधी जानकारी

+

*1040. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बसुमतारी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने देश के प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सविस्तार जानकारी एकत्रित करने के लिये विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से सहयोग मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) पंजाब, गौहाटी और सागर विश्वविद्यालयों ने चुने क्षेत्रों में प्रायोजनाओं के अध्ययन को सम्पूर्ण कर लिया है, और उन्होंने सिफारिश की है कि भूस्थल का भूस्थिति संबंधी वर्गीकरण संभव है । तदपि तकनीक को पूरी तरह से लागू कर पाना सुनिश्चित करने के लिए, कई अतिरिक्त क्षेत्रों पर इसका परीक्षण आवश्यक है । अन्य भूस्थिति क्षेत्रों में पाच अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । कुछ अन्य क्षेत्रों में काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है । प्राप्त हुए परिणाम के आधार पर व्यापक विश्लेषण किया जाएगा और विभिन्न भूक्षेत्रों के संबंध में सूचना संग्रहीत करने के लिए किसी प्रणाली को अपनाने की संभाव्यता का परीक्षण किया जाएगा ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the connection between the physiographic details with our defence and the scope of this work ?

श्री अ० म० थामस : इस प्रकार के सर्वेक्षण और अनुसन्धान से उस क्षेत्र विशेष में मुख्यत: यातायात की क्षमता के बारे में पता लग सकेगा । वास्तव में, जैसा इस समय हो रहा है, इसका सम्बन्ध मुख्यत: भूमि के बारे में विभिन्न पहलू जैसे मौसम, चट्टानें, मिट्टी की परत, भूमिगत

जल और भूमि की सतह से सम्बन्धित सैन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने तथा उसे सम्भाल रखने के लिये उपयुक्त वैज्ञानिक तरीकों के निकालने से है। यदि हमारे पास यह अपेक्षित जानकारी हो तो इनसे हमें सेनाओं के आने जाने और अन्य बातों के बारे में बड़ी सहायता मिलेगी।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether any payment is made to the professors and the experts of universities for this work by the Ministry of Defence or the Ministry of Education and what type of any other aid is given to them so that this work is completed successfully and when this work is likely to be completed ?

श्री अ० म० थामस : हम भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था, मौसम-विज्ञान सम्बन्धी विभागों, नलकूप संगठन, भूमि प्रयोग मिट्टी सर्वेक्षण संगठन तथा इस प्रकार की अन्य विभिन्न एजेंन्सियों से सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं और शिक्षा मंत्रालय की सहायता से हम भारतीय विश्वविद्यालयों का उपयोग कर रहे हैं। हमने भूवैज्ञानिकों, रसायनज्ञों, वनस्पतिज्ञों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और इस कार्य को करने के लिये विश्वविद्यालयों को लगभग तीस तीस हज़ार रुपये दिये हैं। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनको भू-विज्ञान, भू-पटल रचना, जल-वायु विज्ञान, वनविद्या, मिट्टी विद्यान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरी तथा विमानव्दारा फोटो विज्ञान से जानकारी है।

श्री स० चं० सामन्त : जिस प्रकार से हिमालय पर्वतारोहण संस्था भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में अनुसन्धान कर रही है उसी प्रकार से यह कार्य प्रतिरक्षा विभाग के अनुसन्धान तथा विकास अनुभाग द्वारा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री अ० म० थामस : अनुसन्धान तथा विकास संस्थान में एक विभाग है। यह विभाग अनुसन्धान तथा विकास संस्थान का इंजीनियरी का भाग है और यह विभाग ही सब गतिविधियों की देखरेख करता है। यह विभाग हाल ही में 7 मार्च, 1964 को बनाया गया है। मैं ने यह पहले ही बता दिया है कि हम सभी एजेन्सियों से सम्पर्क जोड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय शायद इस कार्य के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं क्योंकि, जैसे मैं ने पहले बताया है, शिक्षा की विभिन्न शाखाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है और हम केवल उन विश्वविद्यालयों का उपयोग कर रहे हैं जिन में ऐसा करना सुविधाजनक है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या प्राकृतिक दृश्य सम्बन्धी विवरण एकत्रित करने के लिये विश्वविद्यालयों के साथ साथ पर्वतारोहण संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है और यदि हां, तो सरकार इन सभी संस्थाओं से कैसे लाभ उठा रही है ?

श्री अ० म० थामस : पर्वतारोहण संस्थायें भी इस सम्बन्धी में उपयोगी हैं। परन्तु वे इतना अधिक विश्लेषण नहीं करती हैं। यह अध्ययन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

श्री श्रीनारायण दास : विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों तथा विभिन्न वैज्ञानिकों के कार्यकलापों को समन्वित करने के लिये क्या कोई विशिष्ट समन्वय एजेंसी स्थापित की गई है और यदि हां, तो वह कौनसी एजेंसी है ?

श्री अ० म० थामस : यह एजेंसियां विश्लेषण सम्बन्धी कार्य करती हैं। अन्य समन्वय कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुसन्धान तथा विकास संस्थान के भूप्रदेश निर्धारण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मैं ने पहले ही बता दिया है कि ये विभाग इंजीनियरी निदेशालय के अधीन हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस के क्या कारण हैं कि इस अध्ययन को केवल कुछ ही प्रदेशों तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के हितों तक ही सीमित किया जा रहा है और क्या सरकार ने प्रादेशिक तथा कार्य सम्बन्धी सीमित दृष्टिकोण से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने की बजाय समूचे राष्ट्र के लिये प्राकृतिक भूगोल के सम्बन्ध में एक व्यापक जांच करने के बारे में विचार किया है ?

श्री अ० म० थामस : भूप्रदेश निर्धारण विभाग 1964 में चालू किया गया था। तीन विश्वविद्यालयों ने पंजाब के मैदानों, गोहाटी के उत्तरी प्रदेश तथा सागर के आसपास दक्षिण माला का अध्ययन किया है। वास्तव में हमारा विचार समस्त देश के प्राकृतिक दृश्य का अध्ययन करने का है क्योंकि यदि हम जलवायु तथा चट्टानों की किस्मों के आधार पर अपने देश को भूभागों में बांट देते हैं तो हम ऐसा अपने देश तथा शत्रु के राज्यक्षेत्र में भी कर सकते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस प्रकार से इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग केवल प्रतिरक्षात्मक कार्यों के लिये ही किया जायेगा अथवा क्या यह जानकारी सामान्य जनता को भी उपलब्ध की जायेगी और यदि यह जानकारी सामान्य जनता को उपलब्ध की जायेगी तो यह कैसे उपलब्ध की जायेगी ?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि मैं ने अभी बताया तीन विश्वविद्यालयों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और इन से प्राप्त हुए प्रतिवेदनों का परीक्षण सेना मुख्यालय तथा वैस्टर्न कमान द्वारा किया जा रहा है। हमें इस मामले में कुछ भेद अवश्य करना पड़ेगा। सामान्य जानकारी, जो जनता को दी जा सकती है, जनता को निश्चय ही उपलब्ध की जायेगी परन्तु कुछ जानकारी का प्रतिरक्षा के लिये विशेष महत्व होगा और इसे आम जनता को उपलब्ध कराना ठीक नहीं होगा।

श्री शाम लाल सर्राफ : यह धारणा कहां तक सही है कि चीन के साथ पिछले संघर्ष में लद्दाख तथा नेफा के प्रदेशों के बारे में जो प्राकृतिक दृश्य सम्बन्धी जानकारी थी वह परस्पर विरोधी थी जिस के फलस्वरूप हमारी सेना को काफी हानि उठानी पड़ी, और यदि यह सही है तो अब इसे कहां तक ठीक कर लिया गया है ?

श्री अ० म० थामस : उन्हीं त्रुटियों से बचने के लिये ही तो हम यह सर्वेक्षण कर रहे हैं।

Compulsory N.C.C. Training

\+

***1041. Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether certain suggestions for making N.C.C. a compulsory part of education have been received ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) whether the N.C.C. training will be continued as at present or some changes are proposed to be introduced ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : कुछ विमुक्त श्रेणियों को छोड़ कर डिग्री कालिजों और विश्वविद्यालयों के सबल शरीर अधिस्नातक छात्रों के लिए एन० सी० सी० प्रशिक्षण पहले से अनिवार्य है। छात्राओं के लिए, स्कूल के छात्रों के लिए और अन्य विमुक्त श्रेणियों के लिए यह स्वैच्छिक है। इस संबंध में अनिवार्य शिक्षा के विस्तार के बारे में कोई और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

(ग) वर्तमान एन० सी० सी० प्रशिक्षण में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है, यद्यपि राष्ट्रीय सेवा संबंधी एक विचार है जिसका उल्लेख लोक सभा में उत्तर दिए गए अल्पसूचना संख्या 13 दिनांक 10-12-65 के उत्तर में किया गया है, कि एन० सी० सी० वरिष्ठ डिवीजन के लिए राष्ट्रीय सेवा को स्थान दिया जाए। प्रस्ताव अभी प्रारंभिक विचार विमर्श की अवस्था में है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the military instructors are taken from the Reserve Force or whether they are pensioners only ?

श्री अ० म० थामस : शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिये सेवा कर रहे कर्मचारियों तथा सेवा निवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know the facilities given to the trained cadets for obtaining commission in the Army ?

श्री अ० म० थामस : वास्तव में उन को यही सुविधा है कि वे एन० सी० सी० का प्रशिक्षण जो अब कालेज तथा विश्वविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य है, प्राप्त कर चुके होते हैं। यह कोई विशेष योग्यता नहीं हो सकती क्योंकि कुछ उन्मुक्त श्रेणियों के अलावा यह प्रत्येक विद्यार्थी पर लागू हैं।

श्री बासप्पा : क्या कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एन० सी० सी० प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त राइफलें तथा अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और कुछ मामलों में सेना में कार्य कर रहे अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये नहीं लगाया जाता है ?

श्री अ० म० थामस : उपकरण उपलब्ध करने में कुछ कठिनाई थी परन्तु अब स्थिति संतोषजनक है। अपेक्षित किस्म की राइफलें उपलब्ध कराने के मामले में भी कुछ कठिनाई हुई है और हम इस दिशा की ओर ध्यान दे रहे हैं। अधिकारियों की कमी के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही है क्योंकि कुछ कमी है और इसको पूरा किया जा रहा है।

श्री बडे : क्या यह सच है कि सभी चिकित्सा-कालेजों में एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है ?

श्री अ० म० थामस : यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विद्यार्थी ने एन० सी० सी० का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया है। यदि उसने पहले ही तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर रखा होता है तो उसे अपने आप ही छूट दे दी जाती है।

Shri K. N. Tiwary : May I know whether any cadre has been created of those trained N.C.C. girl students for the appointment of officers for training ?

श्री अ० म० थामस : लड़कियों के लिये यह प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है परन्तु कई लड़कियां यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस समय लगभग 80,000 लड़कियां ऐसी हैं जो एन० सी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं अथवा कर रही हैं। इन लड़कियों को प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष पाठ्यक्रम हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is a fact that the instructors taken under the National Discipline Scheme initiated by General Bhonsle and on which lakhs of rupees have been spent by Government, are being sent back and they are not being engaged for this purpose now ?

श्री अ० म० थामस : इस योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अब तैयार की गई राष्ट्रीय स्वस्थ योजना में मिला दिया गया है और इस धारणा को भी इस में अपना लिया गया है। यह ठीक नहीं है कि इस मामले से सम्बन्धित एक जैसे कई संगठन हो। इसलिये शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is a fact that the rifles and other equipment being supplied to colleges for training purposes are not useful with the result that work is suffering ?

श्री अ० म० थामस : इस मामले के बारे में श्री बागप्पा द्वारा एक ऐसे ही प्रश्न का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। वास्तव में उपकरणों की कमी है, यद्यपि सप्लाई की स्थिति अब संतोषजनक है। उदाहरणार्थ डी० जी० बी० एम० राइफलों की कमी है। जहां कहीं भी कोई कठिनाई है उसकी ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं।

Shri Bagri : May I know whether it is a fact that N.C.C. training course is left before its purpose is served and then another course of training is imparted and if so, whether Government propose to impart training to the students by adopting all means so that this training proves useful and if so, how ?

श्री अ० म० थामस : यह सच है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में प्रशिक्षण का जो स्तर है वह भिन्न भिन्न है तथापि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिये जा रहे प्रशिक्षण का जो स्तर है उसकी सामान्यतया सराहना की गई है तथा विश्वविद्यालय इस योजना में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या एन० सी० सी० प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र के कार्य का कोई अभिलेख रखा जाता है और यदि हां, तो क्या परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करते समय इसका ध्यान रखा जाता है ?

श्री अ० म० थामस : विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करते समय तो शायद इसका ध्यान नहीं रखा जाता है परन्तु एन० सी० सी० गतिविधियों के बारे में प्रत्येक विद्यार्थियों के कार्य का अभिलेख अवश्य रखा जाता है।

Shri Kashi Ram Gupta : The hon. Minister has just stated that N.C.C. training is not compulsory for girl students. May I know whether there is any proposal to make it compulsory for girl students and if so, by what time ? Whether women officers would also be appointed for this purpose ?

श्री अ० म० थामस : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि इसे लड़कियों के लिये अनिवार्य बनाया जाये फिर भी इस प्रयोजन के लिये महिला अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the time by which it would be made be compulsory.

श्री अ० म० थामस : इस प्रयोजन के लिये ग्वालियर में एक संस्था है।

श्रीमती सावित्री निगम प्रश्न के भाग 'ग' का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा के बारे में योजना अभी विचाराधिन है। जब वह जानते हैं कि सदस्य इस प्रकार की सेवा के लिये बहुत इच्छुक हैं, तो क्या मैं जान सकती हूं कि इस में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री अ० म० थामस : जबरी भर्ती योजना के साथ साथ यह योजना भी तैयार कर ली गई है। इस योजना के अधीन सभी युवकों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा विश्वविद्यालय में दाखला लेने से पहले एक वर्ष का अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यह अभी विचाराधीन है कि क्या इस योजना को लागू किया जाये अथवा नहीं। प्रतिरक्षा मंत्रालय की सैनिक मामलों सम्बंधी समिति ने इस पर विचार किया है और जो प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हुई है वह इस पाठ्यक्रम को अपनाने के पक्ष में नहीं है।

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

+

*1042. श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री यशपाल सिंह:
श्री वाल्मिकी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री सिध्देश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्री धर्म लिंगम :
श्री बासप्पा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री सू० ला० वर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री नारायण रेड्डी:
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में नागालैण्ड तथा उसके आस पास के राज्यों में नागाओं द्वारा की गई अनेक हिंसात्मक तथा शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ;

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 15 सितंबर 1965 और 15 मार्च 1966 के बीच नागाओं ने नागालैंड और पड़ोसी राज्यों में जो हिंसात्मक और उपद्रवी कार्रवाइयां की है ; उनका एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–6019/66।**]

(ख) आसाम, नागालैंड और मणिपुर की सरकारें छिपे नागाओं द्वारा की जानवाली गैर-कानूनी कार्रवाइयों को रोकने और नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य सरकारो ने पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस शक्ति का उपयोग करने के आदेश जारी कर दिए है और अगर आवश्यक हो तो वे छिपे नागाओं की हिंसात्मक कार्रवाइयों को रोकने के लिए सिविल प्रशासन की सहायता करने में सुरक्षा सेनाओं का उपयोग कर सकते हैं।

श्री लिंग रेड्डी : क्या कुछ समय से शांति वार्ता के पीछे पड़ौसियों के विरुद्ध तथा राज्य के अन्दर नागाओं द्वारा विद्रोही तथा हिंसात्मक कार्यवाहियों में वृद्धि हुई है।

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि देश में यह भावना फैल गई है कि छिपे नागाओं का नेता तथाकथित नागालैण्ड की फैड्रल सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में, हमारे प्रधान मंत्री के बराबर पद का दावा कर रहा है और इससे नागालैण्ड में नागाओं की हिंसात्मक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन मिल रहा है?

श्री दिनेश सिंह : बराबर पद का दावा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिंकरे : यह देने का प्रश्न नहीं है। क्या वे मांग कर रहे है?

श्री दिनेश सिंह : यही तो मैंने कहा है कि वे बराबर के पद की मांग नहीं कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : In the statement laid on the Table it has been mentioned:

> "The Nagas are reported to be collecting house taxes from the villagers of Sibsagar-Naga Land border as royalty for collection of forest produce from the State Forest of Desoi Valley and Kakadenga".

On the same day Shri Dinesh Singh laid a statement on the Table in which he mentioned that the Nagas who celebrated the Republic Day and hoisted the Flag were not rebel Nagas and they did it with the permission of the Governor. I want to know whether you are leaving the tax collection job on them or you are trying to stop them ?

Shri Dinesh Singh : We are not leaving tax collection to them but we are telling them that tax collection by them is wrong.

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में 15-3-1966 तक विद्रोही नागाओं द्वारा हिंसात्मक कार्यवाहियां दी गई हैं। विद्रोही नागाओं के नेताओं के प्रधान मंत्री के साथ मिलने के पश्चात् क्या इन कार्यवाहियों में कुछ कमी आई है?

श्री दिनेश सिंह : जी हां।

श्री सुबोध हंसदा : छिपे नागा विद्रोहियों ने कई विद्रोही कार्यवाहियां की हैं। क्या इन सभी बातों पर शांति मिशन और छिपे नागाओं के नेताओं से बातचीत की गई है, यदि हां, तो उन नागा नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है जिनके साथ प्रधान मंत्री बातचीत कर रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : छिपे नेताओं और सरकार में अभी वार्ता चल रही है और इस समय इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that the leader of the hostile Nagas has stated that he can talk only to Prime Minister; he is neither prepared to talk to Foreign Minister nor to the Home Minister ?

Shri Dinesh Singh : No, such thing was not there.

श्री हेम बरुआ : एक ओर तो छिपे नागाओं के नेता दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं और दूसरी ओर वे पड़ौसी राज्य नागालैण्ड में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पादरी माईकल स्कॉट, जो नागालैण्ड शांति मिशन के सदस्य हैं, भारतीय हितों के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं—यदि आवश्यक हो तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं—क्या सरकार उसको विनम्रता के साथ यह बताने के लिए तैयार है कि वह यथा-सम्भव-शीघ्र भारत से चले जायें?

श्री दिनेश सिंह : हमने उनको पहले ही बता दिया है कि उनके चिट्ठियां भेजने के कार्य से हम प्रसन्न नहीं हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछते हैं कि क्या सरकार उसको भारत से चले जाने के लिए कहेगी।

श्री दिनेश सिंह : इस समय जब कि बातचीत चल रही है उनको इस समय भारत छोड़ने के लिए कहना ठीक नहीं समझा गया है।

श्री हेम बरुआ : एक और अवसर पर, अभी पिछले सप्ताह ही वैदेशिक-कार्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार पादरी माइकल स्काट की कार्यवाहियों को गम्भीर पूर्वक ले रही है।

श्री दीवान चन्द शर्मा : जो विवरण वैदेशिक-कार्य मंत्री ने सभा-पटल पर रखा है उसमें बहुत ही भयानक चीजें दी हुई हैं। विद्रोही नागाओं ने न केवल समाज-विरोधी और आपराधीक कार्यवाहियां की हैं बल्कि ऐसी कार्यवाहियां जो भारत की प्रतिष्ठा के लिये बहुत हानिकारक हैं। इन बातों को देखते हुए सरकार एक ओर तो बातचीत करने की नीती और दूसरी ओर सैनिक कार्यवाही करने की द्विमुखी नीति को कब तक जारी रखेगी? क्या सरकार उनको सैनिक शक्ति द्वारा रोकने के लिये सख्त कदम उठायेगी, क्योंकि बाकी सब तरीके असफल रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि सदस्यों को पता है, नागा लोगों का एक भाग सरकार के विरुद्ध कार्यवाहीयां करता रहा है। कोई दो साल पहले इस बात का अनुभव किया गया था कि उनके साथ शांतिपूर्ण समझौता किया जा सकता है और तभी से यह बातचीत चल रही है। अभी बातचीत किसी ऐसे स्तर पर नहीं पहुंची कि यह समझा जाये कि बातचीत संतोषजनक रूप से अथवा अन्यथा समाप्त हो गई है। तब तक हमें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यह सच है कि कुछ विरोधी कार्यवाहियां की गई हैं परन्तु सभा को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न ही करना चाहिए। एक बार जब यह सभा नीती निर्धारित कर ले तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री दीवान चन्द शर्मा : कब तक?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विवरण में दी गई घटनाओं की संख्या को देखते हुए, जो कि तीस हैं, क्या सरकार शांति मिशन के कार्यपर पुनर्विचार करेगी।

श्री दिनेश सिंह : यह सब बातें विचाराधीन हैं। युद्ध-विराम को प्रभावकारी बनाने के सम्बन्ध में छिपे नेताओं से कुछ बातचीत की गई है।

श्री बड़े : नागाओं की सभी विध्वंसक कार्यवाहियां के पीछे इस पादरी माइकल स्काट का हाथ है। आप इस पादरी माइकल स्काट को हटा क्यों नही देते जिसने ब्रिटेन में ऐसे लेख लिखे हैं कि नागा कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होना चाहिए?

श्री हेम बरुआ : माइकल स्काट को तुरन्त हटाने के लिए सभा के प्रत्येक भाग से मांग की जानी चाहिए। सभी देशभक्त भारतीयों को, आपके सहित, यह मांग करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

Dr. Ram Manohar Lohia : One of the reasons for the popularity and power of hostile Nagas is that loyal Naga leaders like Shri Ering, Shri Jamir and Shri Reshang Keishing are not being properly utilised and are not given a chance to become leaders of national level. If it is so, what efforts are being made by the Government to remove this short coming.

Shri Dinesh Singh : We are not hindering their leadership. Two of the Members mentioned by the hon. Member are parliamentary secretaries and take full interest in their affairs. Shri Ering does not belong to Naga land, but Shri Jamir takes a good deal of interest.

Dr. Ram Manohar Lohia : The question is not of hindering. The question is why they are not being allowed to become leaders. They may be parliamentary Secretaries; why are they not given higher post.

Mr. Speaker : This question cannot be raised in a supplementary as to why they are not being offered a high post. He has replied about their utilisation.

Shri Dinesh Singh : I have submitted that they are being utilised and they take sufficient interest.

श्री प्र० के० देव : इस तथ्य को देखते हुए कि नागालैण्ड में नागाओं द्वारा तोड़फोड़ की कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं और इससे शांतिप्रिय नागा हतोत्साह हो रहे हैं, सभी इस बात की प्रशंसा करेंगे कि नागा समस्या का शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि विद्रोही नागाओं ने स्वाधीन नागालैण्ड की मांग को छोड़ दिया है और अब वे इस संविधान के अन्तर्गत विशेष स्थान चाहते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया विध्वंसक कार्यवाहियों में अब कोई वृद्धि नहीं हो रही है। जहां तक स्वाधीन नागालैण्ड का सम्बन्ध है, हमारी स्थिति सर्वविदित है। इस सभा में और बाहर भी यह कहा गया है कि भारतीय संघ के भीतर ही नागालैण्ड के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है न कि भारतीय संघ के बाहर।

श्री प्र० के० देव : उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है। क्या विद्रोही नागाओं ने स्वाधीन नागालैण्ड की अपनी मांग को त्याग दिया है ?

श्री बसुमतारी : चूंकि रानी गिडालो के नेतृत्व में नागाओं का एक और गुट बन गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि रानी गिडालो की मांग और तथाकथित नागालैण्ड की फेड्रल सरकार के प्रधान मंत्री, कुमाटो सखई की मांग में क्या अन्तर है ?

श्री दिनेश सिंह : रानी गिडालो अपने आदिम जाति नागाओं के लिए एक पृथक जिले की मांग कर रही हैं। वे 2 या 3 जिलों में फैल गए हैं। वह चाहती हैं कि वे सब एक ही जिले में आ जायें। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं परन्तु जहां तक विद्रोही नागाओं का सम्बन्ध है वे अलग नागालैण्ड की मांग करते रहे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार ने राज्यभक्त नागाओं की एक स्थानीय सेना बना कर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ? यह सेना हमारी सुरक्षा सेनाओं की उचित जानकारी देकर और दुर्गम मार्गों का पता बता कर मदद कर सकती है।

श्री दिनेश सिंह : ग्राम प्रहरियों की एक योजना लागू है और वह काफी संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। इस समय मुझे स्थानीय लोगों द्वारा अधिक भाग लेने के बारे में किसी और योजना का पता नहीं है। परन्तु यह हमेशा हमारे विचाराधीन है।

श्री बासप्पा : विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियों द्वारा की गई कार्यवाहियों से लोगों ने जो हानि उठाई है, क्या उसका अनुमान लगाया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे पास अभी पूरा ब्यौरा नहीं है।

श्री बूटा सिंह : श्री जय प्रकाश नारायण, जो कि शांति मिशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उनके त्यागपत्र के क्या कारण हैं ? क्या ये कारण व्यक्तिगत हैं अथवा किसी मूलभूत नीति से सम्बन्धित हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पहले दिया है। श्री जयप्रकाश नारायण ने शांति मिशन को एक पत्र लिखा था कि वह अब इसमें कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उनको छिपे नागाओं का पूरा विश्वास प्राप्त नहीं है।

श्री बड़े : क्या सरकार ने माइकल स्काट से यह पूछा है कि क्या उन्होंने किसी ब्रिटिश अखबार के सम्पादक को ऐसा पत्र लिखा है कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय ताकत नागा मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि यह भारत के कई अखबारों में प्रकाशित हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, माइकल स्काट ने ऐसा पत्र भेजा है। हमने ऐसे मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की निन्दा की है जो कि हमारा घरेलू मामला है।

श्री रा० बरुआ : क्या नागा शिष्टमंडल के एक सदस्य ने दिल्ली में एक वक्तव्य में कहा है कि वे शांति मिशन के तथा अपने एजेंटों द्वारा शांति प्रस्ताव विदेशों को भी भेज रहे हैं ? क्या शांति मिशन ऐसे कार्य कर सकता है, यदि नहीं, तो क्या किसी एक सदस्य को ऐसा अधिकार प्राप्त है और सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : शांति मिशन को ऐसा कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है और शांति मिशन ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। शांति मिशन के एक सदस्य ने ऐसा किया है और हमने अपनी अस्वीकृति उनको पहुंचा दी है।

श्री हेम बरुआ : यह एक बहुत गम्भीर बात है कि शांति मिशन ने सामूहिक रुप से ऐसा कार्य नहीं किया बल्कि उनके एक सदस्य ने किया है। इस प्रकार की धोकाधड़ी और राजद्रोह के लिए यह कोई उचित बहाना नहीं है।

Shri Bagri : Does the hon. Minister realised that the main cause for reblion within the country, they may be tribals, Nagas or Mizos, is that they do not feel a sense of participation in the affairs of the Country. Have the Government tried to find out the cause for the increase in the rebellion and what steps are being taken to fulfil their basic demands ?

Shri Dinesh Singh : As for Nagas are concerned the Government of Nagaland is constantly working for their progress. I may inform the House that we are working for the welfare of Nagas the same development is being carried out in Nagaland, which is going on in other parts of the Country.

फिजी में संवैधानिक परिवर्तन

***1043. डा० राम मनोहर रोहिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन आज कल फिजी में पृथक् निर्वाचक मंडलों का सिद्धांत लागू करके वहां के लोगों में फूट डालने का प्रयत्न कर रहा है ; और

(ख) इस प्रयत्न को निष्फल करने और उस राज्य क्षेत्र में शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज कराने में सहायक होने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965 के फिजी संवैधानिक सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने फिजी में कुछ संशोधनों के साथ पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के सिद्धांत को चलाए रखने का समर्थन किया है।

(ख) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों का समर्थन किया है जिनमें प्रशासक राज्य से अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि वह फिजी में "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धान्त पर मुक्त चुनाव कराने की व्यवस्था करे और उस प्रदेश के लोगों को संपूर्ण सत्ता प्रदान करने के लिए तात्कालिक क़दम उठाए।

Dr. Ram Manohar Lohia : Have Government given any thought to the rift that is being created by the British bureaucrats and the Australian capitalist between peoples of Indian origin and the native population of Fiji, in the matter of business occupations as also to the evils that have followed due to the adoption of wrong system of electorates in Fiji and if so, the action being taken by the Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : Yes, Sir, We have given thought to this question of discrimination and as I have submitted just now we had raised this matter in the U.N.O. We had also moved a resolution, which we sponsored and which was passed. This resolution says that the people of that place should be given the right of self determination.

Dr. Ram Manohar Lohia : I wanted to know what has been done regarding the discrimination done in the matter of employment, in the industries, and their wages etc.

Shri Dinesh Singh : We had raised the matter in the U.N.O. that the discrimination should be ended and that they should be given equal rights. If they get equal rights, they will be free and the discrimination will automatically cease.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Indians there are also experiencing difficulties in the matter of their religion. They want to receive religions education by Indian Pandits. What has been done by the Government in this regard ?

Shri Dinesh Singh : I cannot say if there is any hindrance in their way of observing their religion, because people come to us for passports etc. for going to Fiji, we issue the passports and they go without any hindrance.

Shri Maurya : The Indians constitute 52 per cent of the entire population there, but still they are given representation, not on the basis of popular vote but on the basis of Casteism. May I know whether in view of this we have raised this matter in the U.N.O. and if not when do we propose to do so ?

Shri Dinesh Singh : In reply to hon. Member Dr. Lohia's question I had submitted that we had raised this matter in the U.N.O.

Dr. Ram Manohar Lohia : Are Government aware that the 'Rutre' news agency always uses the word Indians domiciled in Fiji whereas these two words are used, first, for those persons who are of Indian origin and secondly for those who are originally belong to Fiji and if so, the steps so far taken or proposed to be taken by the Government to check it ?

Shri Dinesh Singh : We have no control over 'Rutre'. That is the policy being persued there and we are fighting that.

श्री श्याम लाल सर्राफ : फिजी द्वीपसमूह राष्ट्रमण्डल का एक एकक है। फिजी में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में राष्ट्रमण्डल को जोरदार ढंग से सूचित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं? रोडेशिया की भांति वहां भी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : रोडेशिया के प्रश्न और इस प्रश्न में कुछ अन्तर है। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने जो प्रस्ताव किया है उसे लोगों के एक वर्ग ने स्वीकार कर लिया है और दूसरे वर्ग ने, जो कि बहुसंख्यक है इसको स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने इस मामले को उठाया है। हमें देखना है कि इसमें क्या प्रगति होती है। मुझे विश्वास है कि अवसर आने पर हम राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भी इस मामले को उठायेंगे।

थुम्बा राकेट परीक्षण

+

***1044. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 दिसम्बर, 1965 के इण्डियन एक्सप्रैस के पृष्ठ पांच स्तम्भ एक में प्रकाशित "थुम्बा राकेट एक्सपेरिमेन्ट्स फेल", 'थुम्बा राकेट का परीक्षण असफल रहा" शीर्षक की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपचारी कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : थुम्बा स्थित विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से 18 दिसम्बर, 1965 को मौसमी जांच के लिए यंत्रों से युक्त भारयोग सहित छोड़ा गया जुडी-डार्ट राकेट अनुमानित ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका, तथा इस कारण लाभप्रद वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठे नहीं किया जा सके । जिन कारणों से राकेट असफल रहा उनकी जांच की जा रही है । असफलता के कारणों को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that our scientists did not completely examine it before launching due to which we did not get success ?

डा० सरोजिनी महिषी : अब तक 25 राकेट छोड़े गये हैं । इनमें से चार राकेटों में सफलता नहीं मिली है । इसके कारणों की जांच 'नासा' तथा निर्माताओं द्वारा की जा रही है । इस विशिष्ट मामले की जांच की गई है । अभी कोई अन्तिम परिणाम नहीं निकला है । इसके अतिरिक्त इसको प्रकट करना लोक हित में भी नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Many days have passed and so far the Government have not completed the investigation. Are Government treating it in casually or they are serious about it.

डा० सरोजिनी महीषी : राकेटों द्वारा भेजे गये संकेतों तथा रडार के पर्दे की सहायता से जांच के उपाय किये जा रहे हैं । स्थानीय विशेषज्ञों ने इसपर अपनी राय दी है । परन्तु 'नासा' और निर्माताओं की सहमति से इसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

Shri K. N. Tiwary : Is it a Departmental inquiry of the causes of failure or a Commission of experts has been constituted which is inquiring into that and if that is a Commission, the personnel thereof ?

डा० सरोजिनी महीषी : स्थानीय विषेशज्ञ मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री जोकिम अल्वा : क्या यह सच नहीं है कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों की अन्तरिक्ष शक्तियों की सहायता से एक सक्षम निदेशक की अध्यक्षतामें युवक वैज्ञानिकों का एक दल, इन अनौखे परीक्षणों को करने के लिये कठिन परिश्रम कर रहा है ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी हां ।

श्री हरि विष्णु कामत : राकेट्री तथा बाह्य अन्तरिक्ष खोज संबंधी अनुसन्धान के समन्वय के लिये भारत ने किन देशों के साथ करार किये हैं और किन शर्तों पर ? क्या किसी देश ने इस अनुसंधान में हमें सहयोग देने से इन्कार किया है ?

डा० सरोजोनी महीषी : मैं नहीं समझती कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि वह चाहें तो इसके लिये सूचना मांग सकती हैं। परन्तु वह यह नहीं कह सकती कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना मांग रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप उनकी सहायता कर रहे हैं।

Land for Families of Soldiers who died in Indo-Pak. Conflict

*1045. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to give agricultural lands for the maintenance of the families of those soldiers who have sacrificed their lives in the recent Indo-Pak. conflict ;

(b) if so, whether the facilities of tube-wells for irrigation of these lands would also be provided ; and

(c) the number of such families who have so far been given land and the average land allotted per family and the location thereof ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कृषि क्षेत्र राज्य सरकारों के नियन्त्रण अधीन हैं। कई राज्य सरकारों ने संक्रिया में मारे गए सेवाओं के सेविवर्ग के आश्रितों के लाभ के लिए ऐसे भूमिक्षेत्र आरक्षित करने का निर्णय किया है।

(ख) तथा (ग) : आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have the Central Government issued instructions to the State Governments to allot to the Families of deceased soldiers lands having irrigation facilities ?

श्री अ० म० थामस : जी, हां। चीनी आक्रमण के शीघ्र पश्चात हमने विभिन्न राज्य-सरकारों से लिखा पढ़ी की थी और उनमें से अधिकांश राज्यों ने भूमि आवंटन के लिये उपबन्ध किया है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have the States been directed to allot land to the dependents of those killed in action in the respective States of the deceased soldiers ?

श्री अ० म० थामस : सामान्यत: हम यही आशा करते हैं कि विशिष्ट राज्यों के व्यक्तियों को भूमि उनके अपने राज्यों में ही दी जायेगी।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार का विचार भूमि आवंटन के इस कार्य को राज्यों को सौंपने की बजाय प्रतिरक्षा मंत्रालय में ही एक ऐसी व्यवस्था करने का है जिससे कि संतप्त परिवारों को जो असुविधा होती है वह न हो ?

श्री अ० म० थामस : इस श्रेणी के लोगों को राहत देने के लिये अनेक लाभप्रद उपाय किये गये हैं। जैसा कि मैंने बताया भूमि का नियन्त्रण तथा प्रबन्ध राज्य सरकारों के हाथ में है। केन्द्र की अपनी कोई भूमि नहीं है। अत: हमको राज्य सरकारों का सहयोग लेना पड़ता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इसके लिये उपबन्ध किया है। उदाहरणार्थ, आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार की सारी बंजर भूमि को प्रतिरक्षा कर्मचारियों की लाभबन्दी के पश्चात् उनको देने के लिये रक्षित की गई है। अन्य राज्य सरकारों ने भी ऐसा किया है। मेरे पास एक पूरी सूची है। क्या मैं इसको पढ़ूं।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, Sir, when the soldiers are directly under the Central Government why they are kept at the mercy of the State Government and why not the Central Government take this work in their own hands ?

Mr. Speaker : The answer has come.

Shri Rameshwaranand : The answer has not come.

श्री अ० म० थामस : इस में सन्देह नहीं कि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। परन्तु यह केन्द्रीय सरकार के पास जो उनकी सेवा की शर्तें हैं उनके अन्तर्गत नहीं आता है। ये अन्य कल्याणकारी उपाय हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के पास उनकी सेवा की शर्तों के अंग नहीं हैं। भूमि के मामले में हमें आवश्यक रूप से राज्य सरकारों का सहयोग लेना पड़ता है।

Shri Rameshwaranand : My submission is that when they are directly under the Central Government, why do the Government not take the land from the State Government and distribute it itself ?

Mr. Speaker : They have no right on the land.

श्री दी० चं० शर्मा : भारत पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति को पाने वालों के आश्रितों को विभिन्न राज्यों में जो भूमि आवंटित की गई है उसका ब्यौरा क्या है और उनको जो अन्य सुविधाएं दी गई हैं वे क्या हैं ?

श्री अ० म० थामस : जैसा कि उत्तर के भाग (ख) और (ग) में बताया गया है यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : कम से कम कितनी भूमि आवंटित की जाये तथा प्रत्येक राज्य में कितने परिवारों को भूमि दी जाये, क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

श्री अ० म० थामस : यह एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है। कुछ राज्यों में तो 5 एकड़ भूमि नियत की गई है और कुछ अन्य राज्यों में 2½ एकड़ भूमि नियत की गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : देश की प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिये क्या सरकारने किसी योजना पर विचार किया है अथवा कोई योजना विचाराधीन है और इस दृष्टि से क्या देश के सीमावर्ती प्रदेशों में वीरगति पाने वाले सैनिकों के परिवारों को बसाने की कोई योजना है ?

श्री अ० म० थामस : भूमि आवंटन के समय इस पर भी विचार किया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह क्या उत्तर है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसपर विचार किया है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक सरकार ने विचार नहीं किया है।

श्री प्र० के० देव : जो सैनिक मारे गये हैं उनके अतिरिक्त लापता सैनिकों की एक बहुत बड़ी संख्या है। क्या लापता सैनिकों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं दी जायेंगी ?

श्री अ० म० थामस : लापता सैनिकों की संख्या 496 है। यदि एक निश्चित अवधि के पश्चात कोई जानकारी नहीं मिली तो उनको मरे हुए माना जायेगा और उनके परिवारोंको वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो अन्य मृत सैनिकों को उपलब्ध कराई जायेंगी।

श्री प्र० के० देव : वह अवधि क्या है ?

श्री अ० म० थामस : लगभग छः मास।

श्री अ० व० राघवन : मृत व्यक्तियों के परिवारों को छावनी क्षेत्रों में भूमि आवंटित करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अ० म० थामस : छावनी की भूमि उपलब्ध नहीं हो सकेगी क्यों कि अन्य विस्तार योजनाओं से भी उसका संबंध है। जहां तक इस मामले के केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने का संबंध है मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकारें और विशेष रूप से पंजाब सरकार पूरा सहयोग दे रही है। हम जिम्मेदारी क्यों लें।

Shri Onkarlal Berwa : In the Jaisalmer area of Rajasthan, which is a desert, the families of the deceased soldiers have been allotted such lands as have no tube well or any other arrangement of water and as a result of which they are not able to cultivate the land. Do Government propose to rehabilitate them by allotting lands somewhere beside Canal ?

श्री अ० म० थामस : मैं मानता हूं कि ऐसी भूमि देने का कोई फायदा नहीं है जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयुक्त न हो। वास्तव में प्रश्न कृषि योग्य भूमि के संबंध में है और फिर सिंचाई सुविधाओं का प्रश्न आता है। सामान्यत: हमें यह आशा करनी चाहिये कि राज्य सरकारें केवल ऐसी भूमि देंगी जो खेती के लिये उपयुक्त हो।

Shri Sheo Narain : Have you given any thought to those areas which provide you with better armymen? In my constituency Pipragautam and Haria tehsils are such as were rebellions tehsils in 57.

If there is canal, we find no water in it, and if there is water the canals are not dug. Will you issue instructions to the State Governments to take care of such places and to make these arrangements for water. etc.

श्री अ० म० थामस : इन प्रश्नों पर वास्तव में भारतीय सैनिकों नाविकों और वैमानिकों के बोर्ड की बैठकों में चर्चा की जाती है। बोर्ड के सभापति स्वयं प्रतिरक्षा मंत्री हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में हैं। मंत्री भी उसमें भाग लेते हैं और इन सब बातों पर विचार किया जाता है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सरकार यह जानती है कि अन्तिम संघर्ष में पाकिस्तानी सेना का जम्मू तथा काश्मीर के जिन क्षेत्रों पर कब्जा था उन क्षेत्रों में वहां पर सेना में जो व्यक्ति काम कर रहे थे वे या तो मारे गये या वे लापता हैं और वे सबके सब बेघर हैं और यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अ० म० थामस : इस संबंध में श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा पुनर्वास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ब्यौरा सभापटल पर रखे गये प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है।

Propaganda Schemes for Agricultural Development

***1046. Shri Yashpal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to acquaint farmers with agricultural development through the medium of newspapers in view of the critical food situation;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) whether Government have also used other media of propaganda than newspapers; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d). While no specific programme has been launched through the medium of newspapers, systematic use of all media including newspapers is being made for keeping the farmers abreast of developments in the field of agriculture.

Audio-visual media being the most suitable for reaching the rural masses, extensive use is being made of radio, films, posters and hoardings, song and drama and other field publicity methods to acquaint the farmer with scientific agricultural methods for increasing production. Special reference may be made of nearly

12,800 Radio Rural Forums set up throughout the country. These Forums are discussion groups of farmers who listen to broadcasts on agriculture and allied subjects, raise queries and undertake action projects for increased agricultural output. In addition, ten agricultural broadcasting units are being set up in certain States for intensification of broadcast of agricultural information. News, stories, feature articles and pictures are also regularly supplied especially to language newspapers which have good circulation in rural areas.

Shri Yashpal Singh : In no other country save India Cowdung is used as fuel. What steps have been taken by Government to bring home to the farmer that it should not be used as a fuel but as a manure? Do Government propose to have an exhibition in this regard ?

Shri Raj Bahadur : This programme mainly relates to the working of the Ministry of Food and Agriculture. The Directorates of their Extension Information Service are in the Centre as well as in the States and this work is being done by them.

Shri Yaspal Singh : Three things, viz. time, cowdung and energy are essential for Cultivation and all these three are destroyed by *hukka*, what steps are being taken by the Government to check the use of *hukka* ?

Shri Raj Bahadur : I am receiving this information from the hon. Member.

Shri Bade : You just now stated that propaganda is made in the regional languages. I want to tell you that the Hindi used for the propaganda in villages and especially in tribal areas, is not at all understood by the people of those areas. The posters are hung upside down. The reason for this is that they are illiterate. Have Government made efforts to make those people understand in their own language ?

Shri Raj Bahadur : In the programmes broad cast by the All India Radio for the rural areas it is specially taken care of that only the languages of the rural areas should be made use of and this is also done. The time of the rural area programmes broadcast in regional languages has been increased from 45 minutes to 90 minutes.

Shri Bade : Regarding the language of Bastar I.....

Shri Raj Bahadur : I will have an enquiry held regarding the language of Bastar. If that is not being done I will give attention to that.

श्री रंगा : क्या सरकार ने सभी प्रसारण केन्द्रों में तथा सभी भाषाओं में ग्राम रेडिओं गोष्टियां गायम की है?

श्री राज बहादूर : जी हां, इसे बहुत उपयोगी पाया गया है। वास्तव में, जैसा कि मैंने अभी बताया 12,800 ग्राम रेडिओं गोष्टियां कायम की गई हैं और प्रसारण प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 30 मिनट के लिये लगभग सभी भाषाओं में किये जाते हैं ?

श्री कंडप्पन : इस प्रयोजन के लिये आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं उन कार्यक्रमों की जांच करने के लिये क्या सरकार ने, प्रगतिशील किसानों की एक तालिका नियुक्त करने की वांछनीयता पर कभी विचार किया है अथवा करेगी ?

श्री राज बहादूर : इस कमी को ग्राम रेडिओ गोष्ठिओं द्वारा पूरा किया जाता है। वहां कार्यक्रम सुने जाते हैं और सुनने के बाद उनपर चर्चा होती है। उन चर्चाओं के परिणाम स्वरुप जो प्रश्न और समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है ताकि जो सन्देह पैदा हो गये हैं उनको दूर किया जा सके।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ईशापुर के आयुध कारखानों के कर्मचारी

*1047. **श्री स० मो० बानर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईशापुर (पश्चिम बंगाल) के आयुध कारखानों में नये भरती किये गये कर्मचारियों को वही मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकर भता नहीं दिया जाता जोकि पुराने कर्मचारियों को मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) : इस मामले में नए भर्ती किए गए कार्मिको और पुराने कर्मचारियों में कोई भिन्न भेद अभिप्रेत न था। परिस्थिति 20 सितम्बर 1966 को सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की संदिग्धता के कारण पैदा हुई। 6 अप्रैल 1966 को एक संशोधन द्वारा यह संदिग्धता अपास्त कर दी गई है, जिस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्मचारी 10 जनवरी 1962 को जारी हुए सरकारी आदेशों के अन्तर्गत भत्तों के अधिकारी हैं, वह मकान किराया भत्ते के स्थान पर जिसके लिए 20 सितम्बर 1965 को जारी हुए आदेशों द्वारा स्वीकृति दी गई थी, उन भत्ते के अधिकारी होंगे, और वह तदनुसार चयन कर सकते है। अब किसी प्रकार की शिकायत के लिये कोई स्थान नहीं रहा।

कलकत्ता में नेताजी की मूर्ति के उद्घाटन समारोह का प्रसारण

*1048. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृबा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में नेताजी की मूर्ति के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आकाशवाणी ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के भाषण का प्रसारण करने के लिये राष्ट्रीय प्रसारण के अन्त:स्मार्क की व्यवस्था नहीं की थी, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का भाषण, सीधे देश भर के केन्द्रो से एक साथ प्रसारित नहीं किया गया, परन्तु इस समारोह को, 23 दिसम्बर, 1965 को, 8 बजकर 30 मिनट पर प्रसारित केन्द्रीय समाचार दर्शन में शामिल किया गया तथा अंग्रेजी की दिन की 3.30 और 6 और रात्रि की 9 बजें की खबरों में तथा हिन्दी की रात की सवा आठ बजे की खबरों में इसे स्थान दिया गया। केन्द्रीय समाचार दर्शन में, जो आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया गया था, स्व० प्रधान मन्त्री द्वारा, इस अवसर पर दिये गये भाषण के अंश सम्मिलित थे।

जम्बिया में शरणार्थियों का पुनर्वास

*1049. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल सचिवालय के माध्यम से जम्बिया की सरकार द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भारत सरकार शरणार्थियों के लिये सहायता तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए अपना एक अनुभवी अधिकारी जम्बिया में भेज रही है ;

(ख) क्या सरकार का तेल देकर भी जम्बिया की सहायता करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) ज़म्बिया को अन्य किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) : अफसर ने 1 जनवरी 1966 को ज़म्बिया में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। उसे भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनियुक्त किया गया है। तेल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सहायता के अन्य उपायों पर सहानुभूति-पूर्वक तब विचार किया जाएगा जबकि ज़म्बिया से उस के बारे में प्रार्थना की जाएगी।

एशियाई नेताओं का सम्मेलन

*1050. **श्री कपूर सिंह :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री प० ह० भील : **श्री सत्य नारायण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया के राजकुमार सिहोंनूक ने एशिया की बकाया समस्यायों को निपटाने के लिये एशियाई नेताओं का सम्मेलन बुलाया है; और

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कम्बोडिया की पत्रिका 'ले सांगकुम' के संस्करण में "टोर्न एशिया" शीर्षक के लेख में, जो अक्टूबर 1965 में प्रकाशित हुआ था, राजकुल मान्य राजकुमार सिंहानुक ने एशियाई "गोल मेज" आयोजित करने तथा एशियाई देशों का संगठन बनाने का सुझाव दिया था।

(ख) भारत सरकार ने इस विषय में कम्बोडिया के राज्याध्यक्ष के विचार देख लिए हैं। जैसा कि सर्व विदित है, भारत सरकार तमाम एशियाई देशों में संपूर्ण तथा स्वतंत्र सहयोग का समर्थन करती है।

Election Propaganda By A.I.R.

***1051. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether certain Members of Parliament have sent a note criticising the election propaganda done from A.I.R. at the time of election of the Leader of the Congress Party in January, 1966 ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No such note has been received, but a statement to that effect appeared in the Press.

(b) and (c). Taking a full and comprehensive view of the news bulletins relating to the election of the leader of the Congress Party in Parliament, the coverage in the view of the Government was factual, prompt and objective.

भारत में बनाय गये हथियारों तथा गोलाबारूद की मांग

*1052. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये गये हथियारों तथा गोला-बारूद की अन्य देशों में कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों में तथा किन शर्तों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : लोक सभा सदन में इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में वांछनीय नहीं समझा गया।

बोरझार में वायु सेना के विमान की दुर्घटना

*1053. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले बोरझार हवाई अड्डे पर वायु सेना के एक विमान की जो दुर्घटना हुई थी क्या उसके परिणामस्वरूप आसपास के गांवों को हुई क्षति तथा जान और माल की हुई हानि का पूरा अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जनक्षति और सेवा की संपत्ति को पहुंची क्षति निर्धारित की गई है। असैनिक संपत्ति को पहुंची क्षति का निर्धारण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अफसरों के विशेष बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) : असैनिकों को देय प्रतिकर की राशि पर अफसरों के विशेष बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा। अन्तरिम उपाय के तौर पर निधन प्राप्त प्रत्येक छः असैनिकों के निकट कुटुम्ब को 500 रुपये की अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर दी गई है। सातवां मारा गया व्यक्ति वायु सेना का एक अनियत मजदूर कर्मचारी था, और उसके निकट कुटुम्बी को वर्कमैन कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अनुसार प्रतिकर दिया जायेगा। मारे गये विमान चालक के निकट कुटुम्बीय को आश्रित-पेन्शन नियमों के अनुसार दी जाएगी।

बर्मा में मिझो आदिम जाति लोगों की गिरफ्तारी

*1054. **श्री यशपाल सिंह :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री बागड़ी :

क्या **बैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने सरकार को सूचित किया है कि उसने कुछ मिजो आदिमजाति लोगों को गिरफ्तार किया है, जो भारतीय सीमा को पार कर के बर्मा में घुस गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें भारत वापस लौटाने के लिए बर्मा सरकार से अनुरोध करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन रंगून-स्थित भारत के राजदूतावास में मिजो कबायलियों के बर्मा में चले जाने की रिपोर्ट के बारे में बर्मा सरकार का ध्यान दिलाया है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस स्थिति में यह सवाल नहीं उठता।

सेना में हिंदी का प्रयोग

*1055. **श्री कंडप्पन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में हिन्दी सभी प्रयोजनों के लिये अनिवार्य है ;

(ख) हिन्दी लिखने के लिये किस लिपी का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) क्या हिन्दी में निपुणता न होने के कारण पदोन्नतियां रोक दी जाती हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रायः देवनागरी लिपि आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट आफ एज्यूकेशन परीक्षा के लिए बैठने वाले अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से उपयुक्त छात्रों को रोमन लिपि में उत्तर लिखने की विशेष अनुमति दी जाती है।

(ग) जी नहीं। सभी उपयुक्त छात्रों की हालत में प्रायः छूट दी जाती है ताकि अगर वह अन्यथा सक्षम हों, हिन्दी का ज्ञान उनके पद में उन्नति या व्यवसाय में उन्नति में बाधा न बन पाए।

नये सैनिक स्कूल

*1056. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में नये सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां तक कब आरम्भ किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : जी हां, मद्रास सरकार ने एक सुझाव पेश किया है कि जनवरी, 1967 के सत्र से आरंभ के कोडैकनाक में एक सैनिक स्कूल खोला जाए, और मामला विचाराधीन है।

छिपे हुए नागाओंका कोहिमा के निकट मुख्यालय

*1057. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "गणतंत्र दिवस" समारोह के उपलक्ष्य में छिपे हुए नागाओं ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा के निकट अपना मुख्यालय स्थापित किया था और वहां सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने शिबिर लगा लिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस नव-निर्मित मुख्यालय को उखाडने के किए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) छिपे नागाओं ने कोहिमा से लगभग तीन मील की दूरी पर एक कैम्प स्थापित किया था। यह कैम्प खाली कर दिया गया है।

विविध भारती से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापन

*1058. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम पुरे :
श्री फिरोडिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम में व्यापार सम्बन्धी विज्ञापन आरम्भ करने का निर्णय किया है, जिसका समाचार 27 मार्च, 1966 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का वास्तविक स्वरुप क्या है; और

(ग) यह कब आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम में व्यापारी विज्ञापन आरम्भ करने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते।

पाकिस्तान के लिये चीन के टैंक

*1059. **श्री गुलशन :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बागडी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1966 को अखबारों में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार पाकिस्तान को चीन से 59 टैंक मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमने अखबारों में रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान को चीन में बने टी-50 टैंक मिले हैं।

(ख) सरकार के ख्याल में यह भारत के खिलाफ भारत-पाकिस्तान की सांठ-गांठ का एक और सबूत है और वह इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

विद्रोही नागाओं और मिज़ो लोगों की गतिविधियों

*1060. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा सरकार के सहयोग से कोई कार्यवाही की है ताकि विद्रोही नागाओं और विद्रोही मिज़ो लोगों की गतिविधियों को रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : हमने बर्मा सरकार के साथ इसके लिए संपर्क बनाए रखा है कि छिपे नागा और मीज़ो लोग बर्मी प्रदेश का उपयोग पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिये गलियारे के रूप में अथवा उसे शरण स्थान बनाने के लिये न करने पाएं। बर्मा की सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है।

पश्चिम जर्मनी की सरकार के प्रतिनिधियों से पत्र

*1061. **श्री रामपुरे :**
श्री पिरोडिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें एक पत्र पेश किया है, जिसमें यूरोप में तनाव को कम करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार के प्रस्ताव दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) "जर्मन संघीय गणराज्य के राजदूत ने 25 मार्च को जर्मन संघीय गणराज्य सरकार का एक नोट" मुझे दिया, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6070/66।)**

(ख) भारत सरकार के विचार में इस प्रलेख को सावधानिपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये।

कीनियां में भारतीय

*1062. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमुना सुल्तान :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 दिसंबर, 1965 को दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर कीनिया में रहने वाले भारतियों ने उस देश की नागरिकता स्वीकार कर लीं; और

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने ऐसा किया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : यह विश्वास किया जाता है कि 12 दिसंबर, 1965 तक लगभग 15,000 भारत-मूल के लोगों ने कीनिया का नागरिकता के लिए अर्जियां दी हैं ।

जापान के प्रधान मंत्री का भाषण

*1063. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 दिसंबर, 1965 को टोकियों में एशियाई संसदीय संघ की बैठक में जापान के प्रधान मंत्री मि० साटो द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने चीन की "बल प्रयोग और विध्वंस पर आधारित" विदेश-नीति के विरोध में संगठित होने की अपील की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या आर्थिक-वाणिज्यिक तथा सैनिक दोनों क्षेत्रों में (जहां तक चीन का संबंध है) जापान के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं कि जापान के प्रधान मंत्री ने 1 दिसंबर, 1965 को एशियाई संसद् सदस्यों के संघ के सम्मुख एक भाषण दिया था। इन रिपोर्टों के अनुसार, यह भाषण, जिसमें चीन की "शक्ति और तोड़-फोड़ से समर्थित" विदेश नीति के विरुद्ध एक हो जाने की बात कही गई थी, प्रधान मंत्री साटो ने नहीं दिया था, बल्कि एशियाई संसद सदस्यों के संघ के प्रधान जापान के पूर्व प्रधान मंत्री श्री नोबुशिके किसी ने एशियाई संसद् सदस्य संघ की पहली आम सभा के समक्ष दिया था ।

(ख) और (ग) : भारत और जापान के बीच निकट और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और हम इन संबंधों को आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में और भी समुन्नत करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करते रहे हैं ।

Nationalization of Land in Burma

*1064. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Burma Government have nationalised land in that country ;

(b) if so, the estimated value of the property in Rupees of those Indians who have settled there or who have returned to India ; and

(c) the manner in which the Indians who are coming to India can bring their money which they have invested on lands and houses or which they have deposited in the Banks there ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are not in a position to give the estimated value.

(c) The question of repatriation of Indian assets in Burma is at present under discussion between the Government of India and the Government of Burma.

Rehabilitation of Refugees From Sikkim and Tibet

***1065. Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have started a collective farming scheme for the rehabilitation of refugees from Sikkim and Tibet; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) There are no refugees from Sikkim. There is no collective farming scheme for Tibetan refugees also, though a number of them have been rehabilitated on land in settlements at Bylakuppe (Mysore), Chandragiri and Mainpet (Madhya Pradesh).

(b) Does not arise.

Broadcasts by Political Parties during General Elections

***1066. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shrimati Savitri Nigam :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the question of providing opportunity to the parties to make their policy broadcasts from All India Radio during the General Elections has been considered ; and

(b) if so, the principles which have been laid down therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir. It will depend upon the all-India political parties agreeing among themselves, in consultation with the Election Commission, on the principles of allocation of available broadcasting time and facilities.

(b) Does not arise.

भारत द्वारा क्षेत्र खाली न किये जाने के बारे में पाकिस्तान का आरोप

***1067. श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि भारत ने जम्मू और स्यालकोट के बीच घुमला नाला क्षेत्र में तीन इलाके खाली नहीं किए हैं ;

(ख) क्या यह विवाद संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : ताशकंद घोषणा के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को उन ठिकानों से हटाना था जो 5 अगस्त, 1965 को उनके अधिकार में थे। सेनाएं हटा ली गई हैं। भारत के स्थल सेनाध्यक्ष और पाकिस्तानी सेना के प्रधान सेनापति के बीच जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार 5 अगस्त, 1965 की स्थलीय स्थिति के बारे में अगर कोई संदेह उठ खड़े हों, तो वे स्थानीय कमांडरों के बीच आपसी बातचीत से तय किए जाएं। पाकिस्तानी के सियालकोट जिले और भारत के जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल मिलाकर लगभग 36 एकड़ के तीन छोटे-छोटे इलाकों को ले कर मतभेद हो गया। बहरहाल, इस मामले पर स्थानीय कमांडरों ने बातचीत की और परस्पर सहमत निर्णयों के अनुसार ठिकानों में आवश्यक समंजन (एडजस्टमेंट) कर दिया गया।

पेंकिंग में भारतीय कार्यवाहक राजदूत का स्वागत समारोह से उठ कर चले जाना

*1068. **श्री हेम बरुआ :**

श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1966 की रात्रि को पेकिंग में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत समारोह से भारतीय कार्यवाहक राजदूत उठ कर चले गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के उप-प्रधान मंत्री द्वारा भारत के विरुद्ध कुछ बातें कह जाने के कारण उन्होंने ऐसा किया ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो स्वागत समारोह में भारत के विरुद्ध क्या बातें कहीं गई थीं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) चीन के उप-प्रधान मंत्री सिंह फू-चीह ने कहा "जब भारत ने उस पर (पाकिस्तान) हमला किया तब समूचे देश ने एक हो कर बहादुरी से मुकाबला किया, हमलावर को खदेड़ दिया और राज्य की प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय सम्मान को बचाए रखा। चीन की सरकार और वहां की जनता पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों द्वारा हमले के विरुद्ध किए गए संघर्ष की दृढ़ता से समर्थन करती है और काश्मीर के लोगों द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष किए जाने का भी समर्थन करती है"।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो का भाषण

*1069. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में भूट्टो के इस भाषण की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताशकन्द घोषणा पाकिस्तान को काश्मीर के आत्मनिर्णय के संघर्ष का समर्थन करने से नहीं रोकता ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये पाकिस्तान ने अग्रेसर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो ताशकन्द घोषणा के बाद की इन घटनाओं के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इस बात को नोट किया है कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए और उपाय बरतना नहीं चाहता।

(ग) हालांकि हमें पाकिस्तान के इस रवैये के प्रति खेद है, तो भी हम ताशकंद घोषणा पर अमल करने के लिए बराबर डटे रहेंगे और इस बात पर जोर देते रहेंगे कि पाकिस्तान भी उस घोषणा के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे।

आसाम में राष्ट्रीय छात्रसेना दल की राज्य सलाहकार समिति

3492. श्री राम हरख यादव : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम राज्य के लिये राष्ट्रीय छात्रसेना दल की राज्य सलाहकार समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) समिति की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) समिति का संगठन 12-3-1966 के भारत के राजपत्र के भाग दो अनुभाग चौथे में प्रकाशित एस० आर० ओ० अधिसूचना संख्या 53, दिनांक 26 फरवरी, 1966 में दर्शाया गया है।

(ग) एन० सी० सी० की राज्य मन्त्रणा समिति के सत्ताधिकार और कार्य एन०सी०सी० रूल्ज़ 1948 के नियम 43 उपनियम (2) में दिए गए हैं, जो भारत सरकार द्वारा एन०सी०सी० अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 31, 1948) के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे।

Gallantry Awards to Military Personnel from Rajasthan

3493. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of military personnel belonging to Rajasthan who were awarded 'Vir Chakra' and 'Mahavir Chakra' in the fight against invasion of Kashmir in 1948 ; and

(b) the details of the financial assistance and grants given to them ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The names of the recipients of Maha Vir Chakra and Vir Chakra for gallantry in the J & K operations in 1947-1948 who belonged to Rajasthan, are given below :—

Maha Vir Chakra :

1. 20714 Hv. Chuni Ram.
2. 2831725 Rfn. Dhunkal Singh (Posth.).
3. Lt. Kishan Singh Rathor (SS-13659).

Vir Chakra :

1. IO-48118 Jem. Megh Singh.
2. 2831596 Hav. Hazari Singh (Posth.).
3. 2831646 Rfn. Rawat Singh.
4. IO-57421 Jem. Sanwal Ram.
5. 16579 Hav. Richhpal Ram.

6. 2831307 Hav. Chhote Singh.
7. 18495 Nk. Chhog Singh.
8. 2828399 Rfn. Hanumana Ram.
9. IO-13629 Sub. Gopal Ram.
10. IO-56215 Sub. Gugan Ram.
11. 13542 Nk. Birbal Ram.
12. 18775 L/Nk. Ladhu Ram (Posth.).
13. Lt. N. A. Sallik (IC-3929).
14. 2930990 Nk. Ram Sarup.
15. 2931296 L/Nk. Hanuman Ram.
16. 2933717 Sep. Ram Singh.
17. 2931380 Sep. Chothe Ram.
18. IO-61394 Jem. Basanta Ram.
19. 3030697 Sep. Budh Ram (Posth.).

(b) JCOs/OR among them were paid monetary allowance by the Central Government at the rate of Rs. 30 p.m. for Maha Vir Chakra and Rs. 20 p.m. for Vir Chakra. Commissioned Officers were not entitled to these allowances. In addition to the allowances paid by the Central Government, the following rewards were sanctioned by the Rajasthan Government to the winners of Maha Vir Chakra and Vir Chakra (including Commissioned Officers) who were domiciled in that State :

(i) **Maha Vir Chakra** . . .	Rs. 2,000 or 25 bighas of irrigated or 50 bighas of un-irrigated land.
(ii) **Vir Chakra**	Rs. 1,000 or 12½ bighas of irrigated or 25 bighas or un-irrigated land.

Important Papers Left behind by an Army Officer

3494. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shrimati Savitri Nigam :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the extent of truth in the fact that during the recent Indo-Pak conflict, an Army Officer ran away leaving important papers and material;

(b) the action taken against this Officer ; and

(c) the nature of papers and material he left and the loss India suffered due to that?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). Troops led by an officer advancing into enemy territory were counter-attacked and were forced to retreat. In the process a vehicle containing the personal diary of the officer and some other papers was left behind. The officer was removed from his command, as the burden and responsibility thereof was felt to be beyond his capacity. His request for immediate retirement was later accepted. The loss of the documents was not of any material consequence.

Plan to Capture Lahore and Sialkot

3495. Dr. Ram Manohar Lohia : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when our forces crossed the International Boundary on the 6th September, 1965, a plan was prepared to capture Lahore and Sialkot;

(b) whether it is also a fact that on the advice of some friendly countries that the Indian Forces should not advance upto that point, this plan was abandoned; and

(c) if not, whether this plan was abandoned due to incomplete preparations or to avoid loss of life and property ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) Our purpose was mainly to draw out Pakistani armour and fighting potential and blunt its striking power. We did not covet any part of Pakistani territory and no plans, as such, were made to capture Lahore or Sialkot.

(b) and (c). Do not arise.

Aerodromes in Rajasthan and Kutch

3496. Dr. Ram Manohar Lohia : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as regards military and civil aerodromes in the areas of Rajasthan, Kutch and North-Western Gujarat, our army and air force were at a disadvantage as against Pakistan during the Indo-Pak. conflict; and

(b) If so, the steps being taken by Government to remove such shortcomings ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). Suitable steps are being taken to rectify whatever shortcomings had come to light during the last-Indo-Pakistan conflict, It is not in the public interest to disclose details of the shortcomings and the steps that are being taken to remove these shortcomings.

Firing by East Pakistan Rifles

3497. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bagri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1506 on the 29th November, 1965 regarding firing by East Pakistan Rifles and state :

(a) whether there has been any outcome of the protest note sent by Government to Pakistan on the 19th November, 1965; and

(b) if not, the reaction of Government thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) As the situation along the India-East Pakistan border has stabilized as a result of agreement between the military authorities of India and Pakistan, the object of our protest, namely, prevention of firing incidents, has been achieved.

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

3498. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक औद्योगिक परियोजना संगठन स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये कुल कितनी सहायता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास सोसायटी (टिबेटन इन्डस्ट्रियल रिहेबीलिटेशन सोसायटी) नामक एक धर्मार्थ सोसायटी हाल ही में रजिस्टर की गई है ।

(ख) अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। उक्त सोसायटी ने अभी तक सक्रिय रूप से किसी प्रायोजना को नहीं उठाया है। वह कुछ योजनाओं पर विचार कर रही है जिन्हें अभी तक अंतिम रूप भी नही दिया गया है।

मद्रास में अणु शक्ति केन्द्र

3499. श्री दलजीत सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** 20 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट स्थापित किये जाने वाले अणु शक्ति केन्द्र के लिये कनाडा ने भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं

3500. श्री दलजीत सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में भारतीय वायु सेना के विमानों की कितनी दुर्घटनाएं हुई और उन में कितने विमान चालक मरे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : जनवरी से मार्च 1966 तक की अवधि में भारतीय वायु सेना के 9 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिन में तीन विमान-चालक मारे गए थे।

कीनिया में भारतीय लोग

3501. श्री कोल्ला वेंकेया :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीनिया में रहने वाले भारतीयों ने किस अनुपात में कीनिया के नागरिक तथा गैर-नागरिक भारतीयों के रूप में अपना पंजीयन करवाया है ;

(ख) क्या भारतीय आधार वाले बैंकों तथा बीमा समवायों के आधार पर कीनिया में रहने वाले अफ्रीकी लोगों के सहयोग से निर्माण करने वाले उद्योगों में स्थानीय भारतीय व्यापारियों को लगाने के लिये कीनिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से बनाये

गये 'संघटन तथा विकास संबंधी कार्यकारी दल' ने कीनिया के लोगों में भारत के विरुद्ध कोई संदेह पैदा कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से कीनिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ख्याल है कि कीनिया में रहने वाले 8 प्रतिशत से कुछ अधिक लोगों ने कीनिया की नागरिकता के लिए अर्ज़ियां दी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उटता।

काश्मीर में टेलीविजन कार्यक्रम

3502. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन विस्तार कार्यक्रम में काश्मीर को शामिल नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उस राज्य में टेलीविजन लगाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : फिलहाल सीमित साधनों के कारण केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कानपुर में ही टेलीविजन लगाने का प्रस्ताव है। बाद में हमारी योजना शेष राज्यों की राजधानियों में टेलीविजन लगाने की है, इसमें हम श्रीनगर और अहमदाबाद को प्राथमिकता देने का प्रयत्न करेंगे।

Powerful Transmitter at Patna Radio Station

3503. Sri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to instal more powerful transmitter at Patna Radio Station;

(b) if so, by what time and the capacity of the new transmitter; and

(c) the extent of population likely to be benefited therefrom?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (c). No, Sir. However, and auxiliary centre is being installed at Bhagalpur which will carry the same programmes as that of Patna. By addition of this transmitter, approximately 20 lakhs more people will be able to listen to Patna programmes.

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

3504. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तिब्बती शरणार्थियों को अब तक बसाया नहीं गया है ; और

(ख) उनके पुनर्वास के संबंध में वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग 20,000।

(ख) मैसूर में 4,000 और तिब्बती शरणार्थियों, मध्य प्रदेश में 1,000 और बिहार में 500 तिब्बत शरणार्थियों की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। तिब्बती शरणार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए लघु और मध्यम आकार के उद्योगों की योजनाएं बनाने और उनपर अमल करने की दृष्टि से एक औद्योगिक पुनर्वास सोसायटी की स्थापना की गई है। 1,000 और तिब्बतियों को भूटान में फिर से बसाया जा रहा है और लगभग 4,000 तिब्बतियों को सिक्किम में बसाने की योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

Explosion in Ordnance Factory, Kirkee

3505. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 4 persons were injured as a result of an explosion which took place in Kirkee Ordnance Factory on the lst February, 1966; and

(b) If so, the causes of the explosion?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Yes, Sir; four persons were injured as a result of an accident which occurred in the Ammunition Factory, Kirkee on 1-2-1966 two of the injured succumbed to their injuries later.

(b) A Board of Enquiry has been constituted to investigate the matter. The report of the Board is awaited.

भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर किया गया व्यय

3506. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को नजरबन्द रखने पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ख) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य पर खर्च की गई राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : पाकिस्तानी युद्धबन्दियों के नियन्त्रण पर उठा खर्च केन्द्रीय सरकार ने वहन किया था, और खुराक, वस्त्रों, नकद भत्ते और अन्य सुख-सुविधाओं पर सम्मिलित वह कुल लगभग 1,98,000 रुपये थे।

Code of International Law

3507. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee to prepare a Code of International law has been set up by the United Nations Assembly;

(b) whether it is also a fact that Dr. K. Krishna Rao of his Ministry had been elected as Chairman of the Committee; and

(c) If so, the names of countries whose representatives proposed his name and also of those who supported him?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) The United Nations General Assembly at its XVIIIth session in 1963 appointed a 27-Member Committee (including India) to consider certain principles of International Law concerning frinedly relations and cooperation among States, in order to facilitate their progressive development and codification. The Committee was reconstituted at the XXth session of the General Assembly and India continues to be a member of this body.

(b) Dr. K. Krishna Rao was elected as Chairman of the Committee at the session which commenced in New York on the 8th March, 1966.

(c) Dr. K. Krishna Rao's name was proposed by Mexico and seconded by Australia, Poland, the United Kingdom, the United States and the U.S.S.R. The election was unanimous.

बड़ोदा में सैनिक बैरकों में विस्फोट

3508. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मार्च, 1966 को ई० एम० इ० स्कूल, बड़ोदा (गुजरात) की पुरानी सैनिक बैरकों में हुए विस्फोट में कुछ मज़दूर, जिनमें कुछ महिलाएं और एक बच्चा भी था, मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण कुल कितने व्यक्ति मारे गये और ;

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) 4।

(ग) उल्लिखित हथगोला ई०एम०ई० स्कूल (उत्तर) द्वारा 1963 से अधिगृहित वास्य बैरक में फटा था। लगता है गोला उन यौनिटों में किसी एक को जारी किया गया था जो 1962 तक उन बैरकों में रही। मज़दूरों में से एक ने जो बैरक के मट्टी के फर्श को, सीमेंट का बनाने के लिए, खोद रही थीं, उस गोले को उस में दबा हुआ पाया। उस ने उठा लिया, और उस पर अपनी चप्पल रख कर अपनी खुरपी से अपनी चप्पल में कील ठोकने के लिए उसे मारना शुरू कर दिया। फलस्वरूप हथगोला फट पड़ा जिस से चार व्यक्ति मर गए।

Library in Indian Embassy in Nepal

3509. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly fifty per cent of the books in the library of the Indian Embassy in Nepal are missing;

(b) if so, the official held responsible for this; and

(c) the action taken or proposed to be taken in this regard?

The Minister of External Afiairs (Shri Swaran Singh) : (a) In 1961 at the time of stock-taking of the Nepal Bharat Sanskritic Kendra, Kathmandu, it was discovered that 40 per cent of the books in the library costing Rs. 14,384·60 were missing. The loss was due to the non-return of books, irregular maintenance of the stock-registers and the normal wear and tear of books.

(b) &(c). The locally recruited Librarian, who resigned soon after the stock-taking, was found responsible, but no action was taken against him in the public interest on the recommendation of the Mission.

To organise this library properly, an India-based Librarian was appointed. The Mission has also been instructed to conduct stock-taking of books at regular intervals and remedy the defects discovered during physical verification. The Mission have also introduced a security deposit scheme to prevent losses in future.

Libraries in Indian Missions at Istanbul, Damascus and Vientiane

3510. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that irregularities have been noticed in regard to the up-keep of books in the Libraries in the Indian Missions at Istanbul, Damascus and Vientiane; and

(b) if so, the action taken against the employees concerned and the measures adopted to improve the position?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Public Accounts Committee in their 20th Audit Report (Civil) pointed out certain irregularities in the entries made in the stock registers of these libraries. They recommended that the defects in the stock registers be remedied and periodical physical verification of the books be undertaken to keep watch on losses.

(b) We have been issuing instructions to the Missions from time to time asking them to maintain their libraries properly and to conduct stock-taking of the books annually. We have also suggested the introduction of a security deposit scheme or some other scheme suited to their region to keep check on losses. Steps taken to remedy irregularities in the Missions in question are explained below:—

(i) *Istanbul* : A new accession register has been provided to them and all entries of the books received and purchased by them are being made therein. To complete physical verification of the books, the Mission suggested the employment of a whole-time or part-time trained librarian. In view of the ban on creation of new posts, their proposal could not be agreed to. They have, however, been asked to carry out the stock-taking with the help of the existing staff.

(ii) *Damascus* : Consequent to physical verification, the Mission found that 50 publications and reports, mostly produced by the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting and received by the Mission between 1952 and 1955 and meant for wide publicity were not entered in the library Accession Register, but were distributed in the interest of publicity. Since these publication s were put to good use, no further action was considered necessary.

(iii) *Vientiane* : Tne Mission has reported that all books and publications not entered in the library stock register have since been entered and the books issued and overdue for return, have been received back. The books are now being issued according to the set procedures. There has been no loss.

Libraries of Indian Missions Abroad

3511. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in many cases the stock-taking of books kept in the libraries of the Indian Embassies abroad had not so far been done;

(b) if so the reasons therefor; and

(c) the necessary steps being taken by Government for the purpose?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) & (b). Out of 50 libraries attached to our Missions abroad, we have received stock-taking reports for the year 1965 from 25 Missions. Six Missions have expressed their inability to conduct physical verification of library books due to shortage of staff and burden of other work and reports/replies from 19 Missions are still awaited.

(c) Missions are being constantly asked to complete the stock-taking. In the case of Missions who complain staff difficulties, they have been asked to seek the help of the staff in the Chancery and complete the job.

Libraries of Indian Embassies in Beirut, Addis Ababa, Cairo, Etc.

3512. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many books from the Libraries of the Indian Embassies in Beirut, Addis Ababa, Cairo, etc. have been given a loan for many years and have not been returned to the Libraries nor any steps have so far been taken to secure their return;

(b) if so, the value of the books involved; and

(c) the steps being taken by Government for their restoration?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Missions mentioned specifically in the question and nine other libraries attached to our Missions abroad reported loss of books due to non-return by the borrowers or otherwise.

2. All efforts were made to retrieve these books. Repeated reminders were sent to the borrowers and when these failed efforts were made to contact the borrowers personally. Only when all these endeavours failed, the books not returned by the borrowers were treated as lost.

(b) & (c). The value of the books lost by ghese Missions on this account is as under :—

Sl. No.	Missions	Amount in Rs.
1	Embassy of India, Beirut . . .	1,090·17
2	Embassy of India, Addis Ababa .	927·90 (value of sixty more books is being ascertained from the local booksellers)
3	Embassy of India, Cairo . . .	624·36

The books lost by the Missions included a large number of Government publications which had only reference value and the utility of these publications diminished or ended with the supply of later editions thereof. The older publications were neither asked for by the Missions nor was it considered necessary to supply duplicates thereof. The question of restoring the other books is under consideration.

India 1965 Diaries

3513. Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Maurya :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be plased to state:

(a) whether it is a fact that there was delay in printing copies of 'India 1965 Diary' and the first lot of its printed copies was found defective;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the copies of the diary had to be despatched abroad through air mail due to the delay on the part of the printers;

(d) if so, the financial loss caused thereby; and

(e) the action taken aginst the persons responsible for it?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) & (b). Yes, Sir. The first lot of 'India 1965 Diary' supplied by the printers were found not strictly upto the mark for distribution abroad and the copies were diverted for sale within the country. Steps were taken to improve the production of the subsequent supplies which resulted in a slight delay.

(c), (d) and (e). Yes, Sir. Copies were airfreighted but no financial loss was incurred as Air India carried these diaries free of charge. A suitable penalty was, however, imposed on the printers for the delay in supply of the copies.

प्रधान सुचना अधिकारी

3514. श्री हेम बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रधान सूचना अधिकारी विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार के निदेशक के पद का भार भी संभाले हुए है,

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि प्रधान सूचना अधिकारी द्वारा अन्य पदों का भार भी संभालने के बारे में हाल के महीनों में पत्र-पत्रिकाओं में कटु आलोचना की गई थी, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को मानती है कि प्रधान सूचना अधिकारी का पद अन्य नियुक्तियों से सर्वथा पृथक रहना चाहिये तथा क्या सरकारका विचार इस सम्बध में कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) मुख्य सूचना अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार के निदेशक का काम भी कुछ दिनों तक संभाल रहे थे। अब उनको इस अतिरिक्त पद भार से मुक्त कर दिया गया है और एक अन्य अधिकारी विज्ञापन और प्रचार निदेशालयके निदेशक नियुक्त कर लिए गए हैं।

(ख) जी, हां। अखबारों में पिछले मुख्य सूचना अधिकारी के कई पद सम्भालने के बारे में कुछ खबरे छपी थी।

(ग) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

स्थलसेना में चुने हुये लोगो की अनिवार्य भरती

3515. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए लोगों को स्थल सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती करने से सम्बन्धित प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अदन में भारतीय आयुक्त का निवास स्थान

3516. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अदन स्थित भारतीय आयुक्त के निवास-स्थान के रूप में प्रयोग में आने के लिये एक भवन खरीदा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत पर वह भवन खरीदा गया है ; और

(ग) उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 4,00,000 रुपए की कीमत पर।

(ग) चूंकि अदन में मजदूरों की हड़तालों और अव्यवस्थित दशा के कारण कुछ जरूरी मरम्मत कराना संभव नहीं हुआ, इसलिए 3 अमला सदस्य और उनके परिवार किराए की बचत के लिए इस मकान में रह रहे हैं।

एक भारतीय दुतावास तथा एक राजदुत के निवास स्थान के लिये फर्नीचर

3517. श्री हरि विष्णु कामत :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित एक भारतीय दूतावास को सप्लाई किये गये फर्नीचर के अनुरक्षण के लिये लगातार वातानुकूल की आवश्यकता पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक भारतीय दूतावास के राजदूत के लिये 46,667 रुपये वार्षिक किराये पर 25 कमरों तथा अन्य सुविधाओं वाला एक नया निवास स्थान किराये पर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्रमशः उस दुतावास तथा राजदुत के नाम क्या है ; और

(घ) सरकार ने प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, एक किराए के मकान में मकान मालिक की शर्त पर ऐसा करना पड़ा है क्योंकि उसने अपने बहुत कीमती निजी फर्नीचर की देखभाल के लिये वातानुकूल (एयर कन्डीशन) यंत्र दिये हैं।

(ख) उस इमारत की स्थिति जिसमें, कहा जाता है कि 25 कमरे हैं, वास्तव में यह है कि वहां दो बड़े-बड़े स्वागत कक्ष, दो मंझले आकार के हाल है जिनमें से होकर किसी भी व्यक्ति को मकान के दूसरे हिस्सों में जाना होता है, एक आफिस का कमरा, एक प्रमुख सोने का कमरा जिसके साथ सज्जा कक्ष हैं, पांच अन्य सोने के कमरे, एक शीशे जड़ा वरजा और अन्य आनुषंगिक कक्ष।

(ग) राजदूतावास या राजदूत का नाम नहीं बताया जाता है क्योंकि इससे संबद्ध देश में सरकार को काफी परेशानी पैदा होगी।

(घ) सरकार को इस मकान के पट्टे की अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ाना पड़ी क्योंकि काफी छोटे मकानों के किराए, जिनमें बिल्कुल साज सज्जा नहीं होती, उन सज्जित

मकानों के किराए से ज्यादा है, जो कि अब दिया जाता है। इसका कारण यह है कि यह मकान राजदूतावास को खास लिहाज करके एक मकान मालिक ने दिया है जो खुद देश से बाहर रह रहा है।

आर्मी आर्डनेन्स कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क

3518. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 को आर्मी आर्डनेन्स कोर में कुल कितने लोअर डिवीजन क्लर्क थे ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1965 को आर्मी आर्डनेंस कोर के कितने लोअर डिवीजन क्लर्क अपने वेतन-क्रम की अधिकतम राशि पा रहे थे ; और

(ग) अगले दो वर्षों में कितने लोअर डिवीजन क्लर्क अपने वेतन-क्रम की अधिकतम राशि पाने लग जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 3,992।

(ख) 2208।

(ग) 156।

संसद सदस्यों तथा विधान सभा-सदस्यों को जीपों का बेचा जाना

3519. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद-सदस्यों तथा विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों को भारत के विभिन्न स्थानों स्थित सैनिक मोटर-गाड़ी डिपुओं से कितनी जीपें बेची गई ;

(ख) जीपें किस मूल्य पर बेची गई ; और

(ग) इन मोटर-गाड़ियों को बेचने से सरकार को कुछ कितनी धन राशि प्राप्त हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 28-2-1966 तक 483।

(ख) तथा (ग) : मेक, माडेल और स्थिति के अनुसार दर 5,136 रुपये से लेकर 9,850 रुपये तक विभिन्न है। 483 जीपों के बिक्रय से प्राप्त हुई कुल राशि 34,05,156 रुपये है।

मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र

3520. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में रेडियो सुनने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या मैसूर की सरकार ने तीन और आकाशवाणी केन्द्र, डेवनगिरि, मंगलौर तथा गुलबर्ग में खोलने के बारे में हाल ही में सरकार से प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : मैसूर सरकार ने बंगलौर में एक नया केन्द्र खोलने की और गुलबर्ग के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की प्रार्थना की है। इस मामले में स्थिति यह है :

भद्रावती के मीडियम शक्ति के ट्रांसमीटर के द्वारा देवनगिरि में प्रसारण की अच्छी व्यवस्था हो गई है।

गुलबर्गा में ट्रांसमीटर लगाने का काम चालू है और आशा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही केन्द्र चालू हो जायेगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में मैसूर में आकाशवाणी का एक और मीडियम शक्ति का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। यह मंगलौर में खुलेगा।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के लोग

3521. **श्री फिरोडिया :**

श्री हरि विष्णु कामत :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2494 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे तदर्थ अनुदानों के अन्तर्गत भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : 13,738 व्यक्तियों (अर्थात् भारतीय सेना और हांगकांग तथा सिंगापुर रायल आर्टलरी के अफसरों और सैनिकों) ने भूतपूर्व आई० एन० ए० सेविवर्ग के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं और वह उस से लाभान्वित होंगे। 284 अन्य व्यक्ति ऐसी ही वित्तीय सहायता के अधिकारी हैं जो उन, भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं के सेविवर्ग के लिए स्वीकृत की गई है जो आई० एन० ए० में शामिल हो गए थे।

जहां तक निर्योग्य हो गए भूतपूर्व आई० एन० ए० सेविवर्ग और आई० एन० ए० में सेवा करते निधन प्राप्त सेविवर्ग के आश्रितों का संबंध है लगभग 6,150 व्यक्तियों को 1949 में यकमुश्त अदायगियां कर दी गई थीं। इसके अतिरिक्त यकमुश्त अदायगियों से ऐसे व्यक्तियों के मामलों में लाभ पहुंचेगा जो भारतीय राष्ट्रीक थे और 24 दिसम्बर 1964 को जीवित थे।

मद्रास में अणु संयंत्र

3522. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री श्रीनारायण दास :

श्री मुथिया :

श्रीमती रेणुका बडकटकी :

श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री मलाइछामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के सहयोग से मद्रास राज्य में एक अणु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे लगाने में कितनी लागत आयेगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जैसा कि सदन को पहले बताया जा चुका है, मद्रास में स्थापित होने वाला परमाणु बिजली घर परमाणु ऊर्जा विभाग तथा एटामिक एनर्जी आफ कैनाडा लिमिटेड के बीच सम्पन्न तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कैनाडा से प्राप्त मूल डिजाइनों के आधार पर मुख्यतः भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया जायेगा। तथापि आयात की जाने वाली सामग्री को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने के बारे में फ्रांस सरकार से बातचीत चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुमान है कि बिजलीघर पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किन्तु, मूल्यवृद्धि आयात करकी दरों में वृद्धि, संयंत्र के डिजायन में परिवर्तन आदि के आधार पर इस खर्च में रद्दोबदल हो सकती है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के कैडेट

3523. **श्री रामचद्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में इस समय राष्ट्रीय छात्रसेनादल के (सीनियर तथा जूनियर दोनों डिवीजनों में अलग-अलग) कुल कितने कैडेट हैं;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में कितनी लड़कियां हैं;

(ग) क्या इस योजना को उड़ीसा राज्य के सब हाई स्कूलों तथा कालेजों में अनिवार्य कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख) : 31 मार्च 1966 को उड़ीसा में एन० सी० सी० छात्रों और छात्राओं की स्वीकृत संख्याशक्ति, प्रत्येक डिवीज़न में इस प्रकार थी :

	एन०सी०सी० वरिष्ठ डिवीजन	एन०सी०सी कनिष्ठ डिवीजन
एन०सी०सी० छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या . . .	26,600	41,000
एन०सी०सी० छात्राओं की संख्या .	1,200	3,000

(ग) तथा (घ) : उड़ीसा सहित भारत भर के कालिजों और विश्वविद्यालयों के केवल अधिकारी पुरुष अधिस्तानक छात्रों के लिए एन०सी०सी० प्रशिक्षण अनिवार्य है, एन०सी०सी० उच्च विद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं हैं। तदापि कनिष्ठ डिवीजन का विस्तार करके उच्च स्कूलों के छात्रों को एन०सी०सी० कनिष्ठ डिवीजन में शामिल होने की अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं।

कामटी में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण

3524. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के स्कूलों तथा कालेजों के कितने पदाधिकारियों ने इस वर्ष कामटी (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय छात्र सेना दल का प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ख) उड़ीसा राज्य के उन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने पर सरकार का कुल कितना खर्च हुआ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 1965-66 में 38।

(ख) एन०सी०सी० अफसर प्रशिक्षण स्कूल कम्पटी को केन्द्रीय सरकार चलाती है, जो देश भर के एन०सी०सी० अफसरों को कमीशन से पूर्व का और नवीकर प्रशिक्षण देता है। किसी राज्य विशेष से प्रशिक्षण के लिए आए अफसरों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया खर्च अलग दे पाना संभव नहीं है। इन प्रशिक्षार्थियों पर टी०ए० और डी०ए० पर उठा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। अनुमान है कि 1965-66 में उड़ीसा सरकार 38 प्रशिक्षण प्राप्त अफसरों पर इन मदों पर 11,765 रुपये खर्च किया होगा।

जर्मन लोक-तंत्रात्मक गणराज्य से प्रतिनिधि मण्डल

3525. श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 25 मार्च, 1966 को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की मंत्रि-परिषद की उपाध्यक्ष, डाक्टर (श्रीमती) मार्गोवेते वितकोव्स्की के नेतृत्व में जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के शिष्टमंडल में 25 मार्च 1966 को आपसी हित के विषयों पर विदेशी मंत्री के साथ बातचीत की थी। यह बातचीत एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझने में सहायक सिद्ध हुई।

जवानों के लिये भूमि का आवंटन

3526. श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री जवानों के लिये भूमि के बारे में 12 अप्रैल 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा (राज्यवार) अब तक कितने जवानों को भूमि आवंटित की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रादेशिक खाद्य निदेशालय के अधीन नियोजित कर्मचारियों की छंटनी

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"भारत सरकार के प्रादेशिक खाद्य निदेशालय के अधीन नियोजित लगभग 16,000 कर्मचारियों की छंटनी"।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं अपने वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6016/66।]**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रसन्नता की बात है कि बयान में यह लिखा है कि जो कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम में जाना नहीं चाहते वह विभाग में रह सकते हैं तथा यदि छंटनी भी हुई तो उनके लिये अलग रोजगार दिया जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार खाद्य निगम अधिनियम में संशोधन करने जा रही है जिसके कारण जो कर्मचारी खाद्य निगम में स्थानान्तरित हों उनका रोजगार बना रहे ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसी मांग पहले भी 19 मार्च को हुई है। इस पर विचार हो रहा है परन्तु सरकार यह गारंटी देने को तैयार है कि इस समय जो सेवा के नियम लागू हैं वही रहेंगे जिसमें कि पेंशन का अधिकार भी शामिल है। रोजगार का लगा रहना तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता भी शामिल है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वक्तव्य में एक बात साफ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ है कि वह लाभ उन्हें मिलते रहेंगे जो अब हैं और यदि आवश्यक हुआ तो खाद्य निगम अधिनियम में संशोधन कर लिया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : जब कर्मचारियों से इस पर बात हो रही थी तो उनके प्रतिनिधि चाहते थे कि अधिनियम में संशोधन हो। इस समय यह विचार है कि अधिनियम में संशोधन किये बिना भी कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार ने कर्मचारियों से पूछा है कि वह अपनी राय एक निश्चित तारीख तक दें और वह अपने इस समय के रोजगार से त्यागपत्र दे दें ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसी कोई निश्चित तारीख नहीं निर्धारित की है। कोई नौकरी में रोक होगी ही नहीं। कर्मचारियों के प्रतिनिधि केवल ऐसी गारंटी को पक्का कराने के लिये अधिनियम में संशोधन कराना चाहते थे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I rise on a point of Order...

Mr. Speaker : There can not be a point in vacuum.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have given notice of a Privilege notice.

Mr. Speaker : But I have not given my consent to it.

Dr. Ram Manohar Lohia : Everywhere it is said that we are law-breaker and in this way you are trying to hide something.....

Mr. Speaker : Please give me in writing whatever you want to say.

सभा पटल पर रखें गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रेस तथा पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरन अधिनियम के अन्तगत अधिसुचना

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) प्रेस तथा पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 20क की उपधारा (2) के अन्तर्गत समाचारपत्रों का रजिस्ट्रीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 5 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 304 में प्रकाशित हुए थे।

(2) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) चलचित्र (सेन्सर-व्यवस्था) पांचवां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 12 फरवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 235 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 236 जो दिनांक 12 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए क्रम संख्या एल० टी०—6017/66 और एल० टी० 6018/66।]**

अनुदानों की मांगें जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय—जारी

श्री काशीराम गुप्त (अलवार) : मंत्रालय की यह रिपोर्ट बहुत खराब ढंग से बनायी गयी है विशेषकर तेल के बारे में। मंत्री महोदय को चाहिये कि सभा को बतायें कि वह 1968 से पहले गैर-सरकारी

क्षेत्र को बढ़ाने की कैसे आशा करते हैं ? ऐसी ही बात हल्दिया के बारे में है। जब तक पूरे तथ्य तथा आंकड़े सामने नहीं आयेंगे तब तक ठीक परिणामों पर नहीं पहुंचा जा सकता।

जहां तक तेल के वितरण का संबंध है उत्तर में हल्के डीज़ल के तेल में तथा कच्चे तेल में चोर बाजारी होती है। और वह भी कोई थोड़ी बहुत चोर बाजारी नहीं बल्कि मूल्य से 30–40 प्रतिशत अधिक तक। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इसके बारे में अब तक क्यों सख्त कदम नहीं उठाया।

पैट्रोल भी यहां अधिक मात्रा में पड़ा है। सरकार को चाहिये कि इसके निर्यात के लिये नई मंडी खोजे अथवा यहां अधिक ट्रक होने चाहिये जिससे पैट्रोल की खपत हो सके।

उर्वरकों के बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे क्योंकि उसके बारे में श्री केशव देव मालवीय ने कुछ सूचना दी है। यह कारखाना जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा वह सरकार के सहयोग से चलेगा अथवा बिल्कुल गैर-सरकारी होगा। मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र में जो उर्वरक कारखाना है उसमें उत्पादन पर बहुत खर्च आता है। क्या कारण है कि हमारे विशेषज्ञों को अभी तक इसका इलाज नहीं मिला। दूसरी बात मूल्यों के बारे में है कि इसका भी हमारी आर्थिक दिशा पर असर पड़ेगा। वह मूल्य कम करना चाहते हैं, इसका क्या कारण है ? सरकार ने तो अभी तक यह बात सदन को बताई नहीं है। उर्वरकों के वितरण के बारे में देश में खराब तरीका है। जनता इसको बदलने की मांग कर रही है। साथ ही हमें गोबर की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। हमें गैस प्लांट लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस में हमारी ईंधन की कठिनाई भी दूर हो जायेगी तथा हमें खाद पर्याप्त भी मिल सकेंगे। आजकल तो लोग उर्वरकों को खाद्यान्न बढाने के लिये नहीं अपितु नक़दी फसल उगाने के काम में लाते हैं।

सारे मंत्रालयों के बीच एक मिली जुली नीति होनी चाहिये ताकि हमारी तेल तथा उर्वरक संबंधी नीतियां सफल हों।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : महोदय सरकार ने जो उर्वरक संबंधी समझौता किया है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उर्वरक की देश की मांग पूरी नहीं कर सके हैं। इसका कारण यह है कि दूसरी योजना में उर्वरक के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम इस से अच्छी योजना क्यों नहीं बनाते। उर्वरक का उत्पादन देश के लिये बहुत आवश्यक है।

पश्चिमी बंगाल में एक बहुत दुःखजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसका मुख्य कारण मिट्टी के तेल के वितरण में कमी है। मैं ने वहां के जिलों में खूब घूमा है और इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि यह इंडियन आयल कारपोरेशन जोकि सरकारी क्षेत्र में है तथा कुछ कालटेक्स और बर्माशैल आदि कम्पनियों में वितरण की खराब नीति है। परन्तु एक गलत समाचार फैलाया हुआ है कि इसके लिये पश्चिमी बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार इसके राशन करने तथा वितरण करने में शर्म महसूस नहीं करती और उसने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखा भी है। उन्होंने तो चीनी का राशन तथा वितरण बहुत पहले कर दिया है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अब इसका राशन कर दिया है और वितरण हाथ में ले लिया है।

अभी पीछे कलकत्ते में कुछ तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों हुई और ऐसी घटनाओं की हमें निन्दा करनी चाहिये। परन्तु यदि कोई वास्तविक कठिनाई जनता की हो तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो कि बनने वाला है उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार आ रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इस कारखाने को शीघ्र पूरा किया जाये और इसमें ढील देने की बात ही नहीं होनी चाहिये। यदि यह पूरा हो गया तो वहां पर पेट्रो-कैमिकल उद्योग फैल जायेंगे क्योंकि इसके लिये वहां उपयुक्त क्षेत्र है। इस संदर्भ में हमें विदेशी मुद्रा की कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि यह हमें फ्रांस तथा कुवत के लोग दीर्घ-कालीन ऋण देने को तैयार हैं। साथ ही रूमानिया की सरकार भी रुपये की अदायगी पर एक कारखाना खोलने को तैयार हो गई है। मुझे आशा है कि यदि हल्दिया का कारखाना चल पड़ा तो यह दूसरे कारखानों के घाटे को भी पूरा कर देगा।

[श्रीमती रेणुका राय]

मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूं कि वह तेल की खोज की नीति पर बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पता चला है कि रूस की सरकार 24 पर गना में तेल की संभावना के बारे में कह रही है और मुझे आशा है कि इस पर कार्य-जारी रहेगा।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : अध्यक्ष महोदय मैं केन्द्र सरकार की आलोचना इस लिये करूंगा कि उसने इस मंत्रालय के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है। इस मंत्रालय को किसी केबिनेट मंत्री के अधीन होना चाहिये।

मैं उन से सहमत हूं जो सरकार की पुनरीक्षित उर्वरक नीति के विरुद्ध हैं। हमारे लिये यह पुनरीक्षित नीति खतरनाक तथा राष्ट्र विरोधी है। इस लिये इन नीति में जो परिवर्तन आया है उस से हम चिन्तित हैं।

प्रारंभ में तो यह नीति थी कि उर्वरक नीति बिल्कुल सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिये। परन्तु अब कहते हैं कि हमें उर्वरकों की आवश्यकता है और वह जैसे भी मिल सके हमें ले लेने चाहियें यदि यह बात मान ली जाये तो हम कहां पहुचेंगे ? इस दिशा में नीति में विदेशों से तथा अमरीकन सरकार के दबाव के कारण परिवर्तन किया गया है परन्तु कोई भी कम्पनी अभी तक उर्वरक कारखाना स्थापित करने नहीं आई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस दिशा में मेरा सरकार से यह कहना है कि वह वही करे जो दुर्गापुर तथा कोचीन में किया था। थोड़ी बहुत कठिनाई होगी परन्तु यह याद रखना चाहिये कि उर्वरक कारखाना अन्त में सोने की खान सिद्ध होगा। वास्तव में असल बात तो यह है कि वह प्रबंध को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मद्रास कारखाने में तो अमरीकण साझेदार ईरानियन आयल कम्पनी को यहां से निकालना चाहते हैं ताकि उनका स्थान ले सकें। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वह बतायें कि यह समाचार सत्य नही है।

मिट्टी के तेल का संकट अभी तक बना हुआ है। मंत्री महोदय तो कहते हैं कि वितरण की व्यवस्था ठीक है। विभिन्न राज्यों के लिये कोटा निश्चित किया हुआ है परन्तु उन्हें भी गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के रहम पर रहना पड़ना है। इसका असल हल यह है कि इंडियन आयल कम्पनी को चाहियें वह गैर-सरकारी कम्पनियों से मिट्टी के तेल का सारा भंडार ले ले और वितरण की ठीक व्यवस्था करें।

मैं पूछना चाहता हूं कि 4 गैलन-दिनों के बारे में क्या हुआ ? हमें समाचार मिले हैं कि 1965 में कोचीन में 4 गैलन टिनों के उत्पादन में कमी की है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ? मंत्री महोदय को इस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिये।

मै यह भी जानना चाहता हूं कि कि फाइटो-कैमिकल कारखाना, जो बनने वाला था, उसका क्या बना ? कही आप को ऐसी भी सरकार मिलेगी जो लोगों से भूमि अर्जन कर ले और लोगों को वहां से निकाल दे तथा 30 लाख रुपया खर्च करने के पश्चात यह कह दिया जाये कि कोई और कारखाना खोला जायेगा। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

अल्वाय में स्थित उर्वरक कारखाने को बिजली देने के बारे में सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ? एसे समय पर जब कि हमें उर्वरकों की बहुत आवश्यकता है, उर्वरक का एक कारखाना इस कारण बन्द कर दिया जाये कि वहा बिजली कम है। इस कारखाने के बन्द होने पर $2\frac{1}{2}$ करोड़ रूपये का घाटा हुआ है।

दूसरे सदन में बोलते हुए मंत्री महोदय ने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों में छंटनी की धमकी का जिक्र किया। ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के नाम पर बहुत से व्यक्तियों को रोजाना इन कम्पनियों से निकाला

जा रहा है। 1960 से 1965 तक तो तेल की कम्पनियों में कार्य करने वालों की संख्या 25.3 प्रतिशत घट गई। मंत्री महोदय बताय कि यह कैसे हुआ कि एक ओर तो वह लोगों को छंटनी कर रहे हैं और दूसरी ओर दूसरों को भर्ती कर रहे हैं ?

क्या यह सच है कि इंडियन आयल कम्पनी ने कलकत्ता तथा बम्बई में बहुत अधिक किराये पर भवन ले रखे हैं। वह अपनी निजी भवन क्यों नहीं बनाते ?

क्या यह सच है कि कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि की जा रही है ? किस क्षेत्र को यह कारखाना तेल देगा ? क्या सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादकों की आवश्यकताओं के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ? क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता इस क्षेत्र के लिये काफी है अथवा उसे बढ़ाना आवश्यक समझा है। उस राज्य में बरोजगारी की भी समस्या है। इस उद्योग से इस समस्या के समाधान में भी थोड़ा सहारा मिलेगा।

इस वर्ष बिजली की कमी के कारण केरल में 80 प्रतिशत बिजली की कमी हुई। इसी कारण बहुत से उद्योग बन्द हो गये और 50,000 कर्मचारियों को रोजगार से हटा दिया गया।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय हितों की वह रक्षा करें।

श्री टे० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी) : सब से पहले मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के काम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वे लोग कई सर्वेक्षण कर रहे हैं। खम्मात की खाड़ी में भी प्रारम्भिक अनुसंधान हो रहा है। इस मास के अन्त तक यह गवेषणा पूरी हो जायेगी। और अब सर्वेक्षण पश्चिमी भागों में आरम्भ किया जायेगा। भूतत्वीय सर्वेक्षण करने वाले लोगों को काफी हद तक सफलता प्राप्त करने की आशा है। वे 'महेन्द्र' नाम के जहाज में काम कर रहे है और आशा है कि कोई लाभदायक वस्तु को खोज निकालेंगे।

मैं उर्वरक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस दिशा में मेरा विचार यह है कि यदि हम कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें रासायनिक उर्वरक का उत्पादन आरम्भ करना चाहिये। कृषकों ने भी इसकी उपयोगिता को महसूस कर लिया है यदि हम खाद्यान्न की कमी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो उर्वरक का उत्पादन आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कुछ विदेशी तथा स्वदेशी गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए आकर्षित करना है। यह भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र की बिलकुल ही उपेक्षा नहीं की गई है।

विदेशों में उर्वरक काफी सस्ते निर्माण किये जाते हैं। यहां उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। विदेशों में इसके निर्माण के लिए सभी प्रकार के आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। यह भी शंका व्यक्त की गई है कि यदि वितरण और मूल्य निर्धारण का काम गैर-सरकारी कम्पनियों को दिया गया तो किसानों के हितों को हानि होगी। परन्तु यदि इस योजना को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जाता है तो शंका का कोई कारण नहीं है क्योंकि स्वयं सरकार कुल उत्पादन के दो-तिहाई भाग का उत्पादन कर रही है और सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह इन कम्पनियों से बातचीत करके इनके उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग ले सके। विदेशों के सुधरे हुए तरीके देश में लागू करने में उर्वरक के उत्पादन की लागत में कमी होगी। इस समय उर्वरक की लागत बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई सुविधाओं, सुधरे हुए बीजों आदि और कीटनाशक औषधियों के उचित समय पर उपयोग करने की नितान्त आवश्यकता है। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड को कीटनाशक औषधियों का अधिक उत्पादन करना चाहिए।

श्री रा० बरूआ (जोरहाट) : इस मंत्रालय का सम्बन्ध तेल और उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण चीजों से है। इन दोनों चीजों का बड़ा सामरिक महत्व है। ये दोनों चीजें और भी कई दिशाओं में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं। मंत्रालय यह निर्धारित करता है कि तेल के उत्पादन, वितरण और मूल्य के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिये। इसका प्रभाव हमारी समूची अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए यह मंत्रालय मंत्रिमण्डल पद के एक मंत्री को सौंपा जाना चाहिये।

[श्री रा० बरुआ]

हमारे देश के तथा विदेशों के निहित स्वार्थ इस बात का प्रयत्न कर रहे ह कि हमारी नीति में परिवर्तन हो। हाल ही में यह तर्क दिये जा रहे थे कि औद्योगिक विकास तथा प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिए तेल अत्यावश्यक है और हमे विदेशी पूंजी तथा जानकारी को किसी भी रूप में यहां आकर्षित करके उसके उत्पादन में तेजी के साथ प्रगति करनी चाहिये। परन्तु यह तर्क का एक ही पक्ष है। जब तक एक दृढ़ नीति नहीं अपनाई जायगी, उन हितों का सामना करना सम्भव नहीं होगा और भारत की स्वीकृत तेल सम्बन्धी नीति में गम्भीर परिवर्तन किया जायगा। जहां तक सम्भव हो विदेशी सहयोग सीमित रखा जाना चाहिये।

देश के हित में यह आवश्यक है कि भूभौतकीय सर्वेक्षण से लेकर पैट्रो-कैमिकल उद्योग समूह तक तेल के विभिन्न विभागों में देश के अन्दर उपलब्ध योग्यता का लाभ उठाया जाये। अभी तक इस सम्बन्ध में उचित समन्वय नही किया है। विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय वेधशालाओं में इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने चाहिये। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि गोहाटी तेल शोधक कारखाने का कार्य यथासम्भव शीघ्र समाप्त हो क्योंकि विलम्ब से लोगों में रोष उत्पन्न हो जाता है।

यद्यपि आसाम में गैस का उत्पादन किया जा रहा है तथापि वहां पर गैस और तेल पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि इस अवसर का लाभ उठाकर गैर-सरकारी उत्पादन उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं तो जहाँ कहीं भी सम्भव हो सरकार को सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने चाहिये। जब यह उद्योग स्थापित हो जायेंगे तो इनको पूंजी प्रधान होने की बजाय श्रम प्रधान होना चाहिये। जिसकी पिछड़े क्षेत्रों को आवश्यकता है।

क्योंकि हमें कम से कम समय में अधिकतम उर्वरक की आवश्यकता है इसको देखते हुए अमरीका के साथ उर्वरक का जो समझौता किया गया है वह आवश्यक था। इस से हमारे देश में उर्वरक उत्पादन के आधुनिक तकनीकी जानकारी भी आ जायेगी जिससे हम उत्पादन लागत को कम कर सकेंगे। परन्तु सरकार को मूल्य सम्बन्धी नीति पर उचित ध्यान देना चाहिये। हमें गैर-सरकारी क्षेत्र के हितों की नितान्त उपक्षा नहीं करनी चाहिये।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसकी अनुदान की मांग भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन तथा उर्वरक इसके अन्तर्गत आते हैं। म उर्वरक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता मैं सभा का ध्यान औषध तथा भेषज उद्योग के विकास की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

1956 के आरम्भ में देश में औषध तथा भेषज उद्योग के विकास की आवश्यकता महसूस हुई थी। इस उद्देश्य को देखते हुए ही इण्डियन ड्रग तथा फारम्यिटिकल लि० स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना के तीन उद्देश्य थे लोगों को सस्ती औषधियां देना, लोगों को औषधियों की अधिक सुविधायें देना तथा देश को जीवन बचाने वाली औषधियों के मामले में आत्मनिर्भर करना है। परन्तु सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के अपने बाईसवें प्रतिवेदन में ड्रग और फारम्यटिकल लि० के कार्य के बारे में अच्छी रिपोर्ट नही दी। उसने बताया है कि बाजार में अधिक मूल्य पर औषधियों बेची जा रही हैं। वे मूल्य संसार में सब से अधिक है। कुछ मामलों में इनको उत्पादकों ने कृत्रिम रूप से बढ़ाया है। इसलिये सरकार को भेषज तथा औषधियों के मूल्य कम करने के लिये कठोर कार्यवाही करनी चाहिय जिससे भारत के रोगियों को अधिक लागत के कारण जान बचाने वाली औषधियों से वंचित न रहना पड़े।

जहां तक हैदराबाद में सिन्थेटिक ड्रग फैक्टरी की स्थापना का सम्बन्ध है समिति ने बताया है कि उसका विचार यह है कि हैदराबाद इसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि गन्दगी के विसर्जन की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। नागरिक जीवन, कृषि आदि समस्याओं के अतिरिक्त औद्योगिक एककों का विकास भी सीमित हो जायेगा। यदि इस कारखाने को समुद्र तट के समीप स्थापित किया जाता तो गन्दगी से उत्पन्न होने वाली समस्या को रोका जा सकता था। जिला अस्पताल के समान एक आधुनिक अस्पताल को शल्य चिकित्सा के 600 उपकरणों की आवश्यकता होती है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी

समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी उपकरणों को उतनी पूंजी से बनाया जा सकता है जितनी मद्रास संयंत्र में लगी हुई है। मंत्री महोदय को स्वयं इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि सभी चीजों का उत्पादन मद्रास में ही हो।

सिन्थैटिक ट्रग के उत्पादन के लिये आवश्यक 85 चीजों में से देश में 53 चीजें उपलब्ध हैं। 'सोया बीन्स' जैसी चीजों का भी आयात किया जाता है। परियोजना की स्वीकृति देते समय यह पता लगाने के लिए और उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्च माल का पता लगाने केलिए योजना नहीं बनाई गई है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन के प्रशासनिक विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कोचीन में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का मद्रास, मैसूर और केरल में समान वितरण हो। जब भी तेल की कमी होती है, मद्रास को प्राथमिकता दी जाती है और समूचे उत्पादन वहां भेजे जाते हैं क्योंकि वहां चोर बाजारी की गुंजाइश है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। केरल में कानूनी राशनिंग है अतः वहां किसी भी प्रकार की चोर बाजारी की सम्भावना नहीं।

अन्त में मैं कर्मचारियों की छंटनी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गैर-सरकारी तेल कम्पनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। दिल्ली में एक कम्पनी ने अपने 41 कर्मचारियों को वातानुकूलित कमरे में कैद रखा। मेरा मतलब यह है कि उन्हें कोई काम न दिया। क्योंकि वह उन कर्मचारियों को फालतू समझती है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। कर्मचारियों के लिय काम की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि कोचीन तेल शोधक कारखाना आरम्भ होने के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी कम्पनियों से लगभग 700 कर्मचारियों की छंटनी की जायगी। मन्त्री महोदय को इण्डियन आयल कार्पोरेशन में कर्मचारियों की नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने चाहियें।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय कि योग्यता और क्षमता के लिए उनको मुबारक बाद देता हूं। मंत्रालय ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों का उल्लेख है और इस दिशा में काफी कुछ किया गया है। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष ने यह बात तो देश को महसूस करा दी है कि तेल में देश को आत्मनिर्भर होना ही चाहिय। अतः देश में तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जो तेल शोधक कारखानें काम कर रहे ह, उनके काम मे तेजी लाई जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही हम देश की आपातकालीन प्रतिरक्षा तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मेरा विचार है कि सरकार जो कुछ कर रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नीति से विचलित कहा जाय। मद्रास तेल शोधक कारखाने में सहयोग की शर्तें विद्यमान अन्य कारखानों से अधिक अच्छी है। तेल नीति के बारे में कहा गया है कि इस मामले में पुरानी नीति पर कायम रहना चाहिए। मेरे विचार में कोई एसी स्थिति निर्माण नहीं हुई कि सरकार अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। मद्रास शोधनशाला ने सरकार का अंश 52.6 प्रतिशत हो गया है। कोचीन में यह अंश 34 प्रतिशत है। मद्रास का प्रबन्धक निर्देशक भी हमारी सरकार ने ही नियुक्त करना था और कोचीन का प्रबन्धक निर्देशक की नियुक्ति सहयोगियों द्वारा की जाती है। मद्रास के मामले में हमने अपनी आधारभूत नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत उर्वरक उत्पादन का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसे भी हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। लगभग साठ प्रतिशत ही प्राप्त किया गया है। यह खेद की बात है कि सरकारी क्षेत्र के छः उर्वरक कारखानों में से तीन पर विद्युत् की कमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उससे एक एसे समय 2.5 करोड़ रूपय की हानि हुई है जबकि हमें उर्वरक की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि उर्वरकों के उत्पादन के बारे में सरकार के नये प्रस्तावों पर ठंडे दिल से विचार किया जाये तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार की स्थापित नीति से अलग है। हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी नीति का मूल्यांकन करना होगा। यह कहना तथ्यों के विपरीत होगा कि अमरीका के साथ हमारा समझौता 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के विरूद्ध है। उस संकल्प में तथा तीसरी योजना में उर्वरक का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में करने की व्यवस्था है। चौथी योजना में भी यही व्यवस्था है।

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

जहां तक मूल्य नियन्त्रण का सम्बन्ध है, ऐसा प्रभाव पैदा करने का प्रयत्न किया गया है कि सरकार मूल्य निर्धारित करने का अधिकार पहली बार छोड़ रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि नाइट्रोजन उर्वरक को छोड़ कर अन्य सभी रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में हो रहा है और गैर-सरकारी कारखाने उन उर्वरकों का मूल्य निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। वितरण भी गैर-सरकारी हाथों में है। उन उर्वरकों की फुट कर बिक्री पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिए अब केवल यही किया जा रहा है कि नाइट्रोजन के अतिरिक्त उर्वरकों के बारे में जो प्रथा चल रही है, उसे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों पर भी लागू किया जाये। इसे अलग रहना तथा दूसरों के हाथ में बिकना नहीं कहा जा सकता। जहां तक इस सुझाव का सम्बन्ध है कि इससे कृषकों को हानि होगी यह नहीं भूलना चाहिए कि 'पैट्रो जोनियस' उर्वरक का 65 प्रतिशत उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है। इसके अतिरिक्त सरकार इसका आयात कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि देश के कुल उत्पादन के 80 प्रतिशत पर इसका नियन्त्रण होगा। स्पष्ट है कि गैर-सरकारी नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र शर्त लगायेगा। इसे पथपरिवर्तन और दूसरों के हाथ बिकना नहीं कहा जा सकता। जहां तक कृषकों को हानि संबंधी तर्क का संबंध है, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि 'नाइट्रोजनस' उर्वरक का 65 प्रतिशत उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है और शेष 35 प्रतिशत में से भी सरकार को 30 प्रतिशत उत्पादन अपने हाथ में लेने की छूट है और साथ ही सरकार को इसका आयात करने का भी अधिकार है। इस प्रकार देश में उर्वरक के कुल उत्पादन के 80 प्रतिशत पर सरकार का नियंत्रण होगा। स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र को अपनी शर्त मनवाने का अधिकार होगा। और यदि सरकारी क्षेत्र 80 प्रतिशत उर्वरक का मूल्य घटा दे तो शेष 20 प्रतिशत उर्वरक का जिसका उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है, भाव अपने आप गिर जायेगा।

इससे अधिक और अजीब सुझाव और क्या हो सकता है जब कहा जाता है कि उर्वरक का स्वयं उत्पादन करने के बजाये इनका आयात किया जाये। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि गैर-सरकारी सहयोगियों को इतना लाभ न दिया जाये जिस से हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैर-सरकारी कम्पनियों को मण्डी-व्यवस्था स्थापित करके इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अनुचित रूप से अधिकार न करने दिया जाये।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति से भेषज के उत्पादन में सरकार की असफलता का पता चलता है। इससे उन्हें चिन्ता होनी चाहिय और इस गलती को सुधारना चाहिये। 8 वर्ष पूर्व रूस के साथ एक करार हुआ था। 5 प्रस्ताव दिये गये थे परन्तु किसी न किसी कारणवश कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। यह शर्म की बात है और आशा है सरकार इस कलंक को शीघ्र ही धो डालेगी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के अन्त तक उर्वरक क्षमता दस लाख टन हो जायेगी और इसका कुल उत्पादन 8 लाख टन का होगा परन्तु हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई। इसके कई कारण हैं जैसे विदेशी मुद्रा का अभाव जो मंत्रालय के बस से बाहर है परन्तु आशा है कि 1967 में जब पांच नये कारखाने चालू हो जायेंगे तब 6 लाख टन की वर्तमान क्षमता बढ़कर 1½ गुना हो जायेगी। 1969 में जब हाल ही में स्वीकृत दुर्गापुर और कोचीन परियोजनाओं में उत्पादन आरंभ होगा तो नाइट्रोजन की क्षमता 3 लाख टन और बढ़ जायेगी। कानपुर में एक कारखाना लगाने का लाइसेंस दिया गया है और 1969 के अन्त तक इसकी क्षमता 16 लाख टन की क्षमता हो जायेगी। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों का उत्पादन भी इस क्षमता में जोड़ा जाये तो हम पुनरीक्षित लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। आशा है कि हम चौथी योजना के अन्त तक 24 लाख टन की क्षमता और 20 लाख टन के उत्पादन का पुनरीक्षित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। यह कार्य पूरा होने पर हम 'उड़ान-भरने' की स्थिति पार करके आगे बढ़ने की स्थिति में हो जायेंगे और तब हम वह सारी आशायें पूरी करने योग्य होंगे जो खाद्य समस्या हल करने के लिये हम से लगाई जाती है।

'फास्फेटिक' उर्वरक के बारे में मुख्य समस्या कच्चे माल, गंधक और 'राक फास्फेट' की उपलब्धि की है। हम गंधक और 'राक-फास्फेट' की खपत घटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिये हम अपनी क्षमता और देश में ही तकनीकी जानकारी को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

सिन्द्री, दुर्गापुर, हलदिया, राउरकेला, तलचेर और बरौनी आदि स्थानों पर उर्वरक कारखाने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है। इस समय यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि देश में किस प्रकार का उर्वरक तैयार किया जाये और कारखानों की क्षमता कितनी हो। इस बारे में निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा।

असम में गैस यद्यपि काफी मात्रा में उपलब्ध है परन्तु समस्या उसके उपयोग की है। इस प्रयोजनार्थ असम में एक अन्य कारखाना स्थापित करने के बारे में 'आयल इण्डिया' और भारतीय उर्वरक निगम कुछ तकनीकी, आर्थिक और सुकरता संबंधी अध्ययन कर रहे हैं। इस बारे में शीघ्र निर्णय हो जायेगा।

केरल तथा पंजाब में उर्वरक कारखानों को बिजली की कमी के कारण बन्द करना पड़ा। केवल इन्हीं दो राज्यों में ही बिजली की सप्लाई पन बिजली पर आधारित है। बरौनी में भी बिजली की सप्लाई में कटौती हुई है। हम सिचाई और बिजली मंत्रालय से इसके लिये प्रार्थना की है क्योंकि अधिक से अधिक उर्वरक-उत्पादन देश के हित में है और इस से विदेशी मुद्रा में बचत होती है। आशा है केरल में तापी-बिजली-घर बन जाने से स्थिति में सुधार हो जायेगा।

उत्पादन कम होने से कई अन्य समस्याओं जैसे माल लाने ले जाने संबंधी, आदि। और अधिक कारखाने स्थापित करने के साथ ही हम उर्वरक की उत्पादन लागत में विदेशी मुद्रा का अंश कम करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। पहले के 13 करोड़ के स्थान पर अब यह 10 करोड़ रह गया है। इसके लिये हम ने एक समिति भी नियुक्त की है। इसकी रिपोर्ट पर, जो बहुत अच्छी है, हम ने कार्यवाही की है। कोचीन तथा दुर्गापुर कारखाने स्थापित करने से विदेशी मुद्रा अनुमान के अनुसार कम हो जायेगी।

कच्चे तेल का उत्पादन कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिये निरंतर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होती है। हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष हमें कटना में तथा जम्बूसर में तेल प्राप्ती हुई है। यह एक उत्साहजनक लक्षण है। अलंकेश्वर में कुल उत्पादन 22 लाख टन का हो गया है और इस वर्ष यह 27 लाख टन हो जायेगा। खम्बात तथा अन्य तेल क्षेत्रों में भी हम सुधार के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है।

'आयल इण्डिया' अपना तेल शोधक कारखाना विकसित कर रहा है। रुद्रसागर, नहरकटिया तथा मोरान में अपने तेल क्षेत्रों के विकास की ओर उसने महत्वपूर्ण पग उठाये हैं। तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग ने रुद्रसागर तथा लकवा और अन्य स्थानों का विकास किया है जो उत्साहजनक लक्षण हैं। खोज और छिद्रण कार्य भी कई अन्य स्थानों पर हो रहा है।

श्री के० दे० मालवीय ने तट से दूर ड्रिलिंग तथा खोज के बारे में बहुत कुछ कहा है। तट मे परे तेल की खोज का कार्य कई देशों ने पिछले 10 अथवा 15 वर्ष में शुरु किया है। इस सम्बन्ध में हमने सब से पहले खम्बात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा कोरोमंडल तट पर कुछ सर्वेक्षण करने के लिए कुछ रुसी तथा भारतीय जहाजों को वहां भजा है। हम तटदूर छिद्रण पद्धति का विकास कर रहे हैं क्योंकि हमें हिन्द महासागर में सफलता मिलने की आशा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना पूरी क्षमता में कार्य कर रहा है। कोयली तथा बरौनी के विस्तार से हमारा आन्तरिक उत्पादन बढ़ जायेगा। कोचीन तेल शोधक कारखाने की क्षमता 25 लाख टन है। वास्तव में यही एक ऐसा कारखाना है जिसकी शुरु में ही इतनी क्षमता है। हम कोयली, बम्बई, कोचीन, मद्रास और हल्दिया आदि में कई तेल शोधक कारखाने स्थापित कर रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने गैस जलाने के बारे में प्रश्न उठाया है। ऐसा कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है जहां गैस जलाई नहीं जाती। हम गैस पटना और कलकत्ता भी भज रहे हैं। अधिक सिलन्डरों के निर्माण के अतिरिक्त, हम उन में सुधार करने तथा उसे उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के अधिक नगरों में देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[श्री इकबाल सिंह]

हम मानते है कि कीटनाशक औषधियों के मामले में अभी आरम्भ ही किया है। उनके बारे में समस्या यह है कि कच्चा माल नहीं मिलता। जब गुजरात, बम्बई तथा बरौनी में पैट्रों-रासायनिक उद्योग समूह स्थापित हो जायेगा तब कच्चा माल मिलने लगेगा। कीट नाशक औषधियों के लिए आवश्यक कच्चे माल का बहुत अधिक आयात किया जा रहा है। हम कुछ अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है ताकि कीट-नाशक औषधियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्री राजाराम (कृष्णगिरि) : यह मंत्रालय देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कावेरी बेसिन के निकट खोज कार्य आरम्भ कर दिया है। उसने कैम्बे के निकट तेल का पता लगाया है। परन्तु कई वर्षों से कार्य की गति बड़ी धीमी है। मंत्री महोदय को उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिये और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को यह सलाह देनी चाहिये कि वह कावेरी बेसिन के निकट अपना कार्य शीघ्रता से निबटाये।

हमारा दल द्रविड़ मुनेत्र कबगम सरकारी क्षेत्र के पक्ष में है। परन्तु सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में बहुत खराब है। जब इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने कार्य आरम्भ किया तो हमने सोचा कि वह निश्चित दर पर समूचे देश में डीज़ल, पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल का वितरण करेगा। परन्तु मिट्टी का तेल केवल नगरीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। ग्रामों के लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। ग्रामों में निवास करने वाले निर्धन विद्यार्थियों को इस से बहुत हानि हो रही है। इसके साथ ही मद्रास में चोर बाज़ार में मिट्टी का तेल काफी मात्रा में मिल सकता है। मिट्टी के तेल की बिक्री में कदाचार को रोकने के लिए मार्केटिंग डिवीजन को विशेष कार्यवाही करनी चाहिये। हाथ से चलने वाले ठेले पुनः चालू किये जाने चाहिये और लोगों को घरों पर ही मिट्टी का तेल मिलना चाहिये।

एस्सो, बुरशेन तथा चागलास का लीक्विड पैट्रोलियम गैस दक्षिण में उपलब्ध है परन्तु इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा बनायी गयी गैस मद्रास में उपलब्ध नहीं है। यह गैस लोगों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यद्यपि इण्डियन आयल कार्पोरेशन सरकारी क्षेत्र में है तथापि वह मूल्य निश्चित करने के मामले में गैर-सरकारी कम्पनियों का ही अनुकरण करती है। मंत्री महोदय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये।

दक्षिण में बहुत कम रासायनिक उद्योग स्थापित किये गये है। उद्योगों के अधिक लाइसेंस उत्तर में लगाने के लिए दिये गये है। रसायनों की आवश्यकता कई वस्तुओं के निर्माण के लिए होती है।

हथकरघा उद्योग में रंगों का प्रयोग होता है। रंग बनाने और आयात करने वाले आम तौर पर कृत्रिम कमी पैदा कर देते है और लाभ कमाते हैं। उसे रोका जाना चाहिये। देश में अधिक से अधिक रासायनिक उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें।

मेरे ज़िले, धर्मपुरी में, टैपिओक की उपज होती है। धर्मपुरी अथवा हरुर में उद्योग चालू किया जाना चाहिये ताकि सैलम में गुलुकोज़ 'डी' तथा दूसरे प्रतिजीवाणु के उत्पादन में टैपिओका का प्रयोग किया जा सके।

उर्वरकों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है। हमारी चौथी योजना में 24 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। इसराइल में उर्वरक प्रयोग के मामले में कृषकों की सहायता करने के लिए अनुसन्धान केन्द्र खोले गये है। यहां भी कृषकों के लाभ के लिए ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहियें।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में पैनिसीलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि के निर्माण की लागत अन्तर्राष्ट्रीय दरों की तुलना में बहुत अधिक है। आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते है। इन औषधियों की दरें कम की जानी चाहिये ताकि जनसाधारण उन्हें प्राप्त कर सके।

Shri Daljit Singh (Una) : The progress achieved by the Ministry of Petroleum and Chemicals during last year is apparent from the report. The Ministry has made

great achievement in many fields. The country could be proud of those achievements. Considerable progress has been made in the production of oil and medicines.

A little difficulty arose in the matter of kerosene oil during last year. The performance of the Ministry regarding maintenance of supply of kerosene oil during Indo-Pakistan conflict is praiseworthy. The Ministry deserves to be congratulated in this matter.

The country is faced with the problem of fertilizers. The performance of the units under the Fertilizer Corporation of India in the matter of production of fertilizers has been commendable. There is scope for improvement in those factories. The Government should expand the existing factories instead of starting new ones. This will result in saving. In that case, the Government will not find it necessary to acquire more land and the farmers will not be put to any difficulty. Farmers will also get cheap fertilizers.

The farmers have been evicted from their land but the land acquired from them for the purpose of setting up fertilizer factories is not being utilised fully. Such land had to be given back to the farmers in the case of Nangal Fertilizer Factory. The Government should acquire land according to requirements so that the crops do not suffer.

A certain percentage of posts in the Nangal Fertilizer Factory should be given to the persons evicted from thier land due to acquisition for the factory. People belonging to seven or eight villages have been evicted from their land which was acquired for Nangal Fertiliser Factory.

Due share in the services in Public Sector undertakings should be given to the Scheduled Castes. Posts are not reserved in those Undertakings. I request the Minister to pay attention to this matter. Posts should be reserved for Scheduled Castes.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The report of the Ministry of Petroleum and Chemicals is disappointing. There is a great shortage of Oil and Chemicals in the country. Unless and until we become self-sufficient in this field, we will be freed from dependence on foreigners. At present we are sending some engineers for training in foreign countries. Their number should be increased. Only then we will be able to achieve self-sufficiency in this matter.

Two or three training colleges have been opened in the country. The purpose is to send lesser number of persons to foreign countries. This purpose is commendable but the Indian Engineers, who have to serve the Government for a specified period according to the terms of the bond they are required to execute, are paid less than the foreign engineers employed by the Government. That disparity should end.

The gas from the wells in Ankleshawar and Cambay is being wasted, but the people of those areas get it at a very high rate while it is sold cheaper in other places. Attention should be paid to this matter.

Six mica factories have been set-up in the country. One factory has been recently set-up but it has not started production yet. The Government is not paying proper heed to the matter of self-sufficiency in food. Cowdung is being burnt in the country. The government should not allow such wastage when we are already short of fertilizers. In order to help in stepping up agricultural production, Government should set up more fertiliser factories.

[Shri Onkar Lal Berwa]

A geologist of America has found phosphate rocks near Massoorie and around Jaisalmer, but no attention has been paid to this matter. Light diesel oil is being sold in blackmarket. It is a matter of regret that the Government has not been able to control the prices of light diesel oil. Deposits of mica have been found in Rajasthan. The Government should pay attention to harness them. There are oil deposits in Jaisalmer and other parts of Rajasthan. Those areas should be surveyed.

The water used in the Nylone factory at Kotah is being diverted to the river at present. The river water is thus being polluted and it is endangering the human and cattle life. That must be stopped and the water should not be discharged into the river.

Shri Tulsidas Jadav (Nanded) : The quantity of oil we need has not been mentioned in the report of the Ministry of Petroleum and Chemicals. It has been given in the report that we have decided to meet our requirement of oil through imports from U.S.S.R. and other countries. The country is facing acute food shortage. It is a matter of great regret that diesel oil is not available for the pumps. It causes a great hardship to the farmers. One cannot understand why such a state of affairs is allowed to continue.

I visited Maharashtra a few days ago. It has been complained that engines are lying idle there and the crops is drying for want of water. The requirement of diesel oil of Maharashtra is not being met. Agricultural production is suffering because of that. The Government should pay immediate attention to this matter.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

The Minister once told me that oil is available in the country. If that is so special attention should be given to make diesel oil available for agricultural purposes. It should be made available at cheap rates. Light diesel oil should be made available to village farmers.

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : इस मंत्रालय का सब से महत्वपूर्ण काम कुछ रासायनिक औषधियां है जो जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके निर्माण के बारे में बहुत उपेक्षा की गई है जिसके कारण उत्पादन बहुत कम हुआ है। मंत्रालय ने उन बड़ी योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की है जिनसे टैट्रासाइक्लोन, स्ट्रैप्टोमाइसीन आदि जैसी जीवन बचाने वाली औषधि यों का उत्पादन देश के अन्दर हो सके। मैं इस मामले पर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस योजना की क्रियान्विति में रुचि लें।

इस देश में अच्छे प्रकार के औजरों की कमी है जिनकी आवश्यकता हमारे अस्पतालों, शफ़ाखानों तथा दवाखानों में है। बहुत से सर्जन मेरे पास आये हैं और उन्होंने शिकायत की है कि अच्छे औजार आयात नहीं किये जाते हैं बल्कि घटिया किस्म के औज़ार आयात किये जाते हैं। अच्छा कार्य केवल अच्छे औजारों से ही हो सकता है। मैं तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि औजार देश में ही बनाये जायें। कई बार हमारे सर्जनों का मुकाबला विदेशी सर्जनों से किया जाता है। जब हमारे देश में औजार ही अच्छे किस्म के नहीं हैं तो फिर मुकाबला भी ठीक नहीं होगा।

अच्छा कार्य अच्छे स्वास्थ्य से ही हो सकता है। इस लिये मैडिकल विभाग के बजट में कटौती मेरी समझ से बाहर है।

हमारे देश में उर्वरकों की भी बहुत आवश्यकता है और इसकी कमी के कारण यहां उत्पादन भी कम हो रहा है। मुझे पता चला है कि जर्मनी में दूसरे दर्जे के कोयले से सस्ता उर्वरक पैदा हो रहा है। यदि ऐसा है तो दूसरे दर्जे के कोयले की तो हमारे देश में भी कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े और ऐसा तरीका बतायें जिस से दूसरे दर्जे के कोयले से उर्वरक बनाया जा सके। हम खाद्यान्न तथा उर्वरक तो आयात करते हैं परन्तु अनुसन्धान पर हम खर्च नहीं करते हैं। हमें अपने अनुसन्धान से यह कार्य करना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : सारे देश के लिये और मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल के लिये एक बहुत आवश्यक प्रश्न मिट्टी के तेल का है। यह ऐसी वस्तु है जिनकी गांवों में भी आवश्यकता पड़ती है। यह बड़े दुःख की बात है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार मिट्टी का तेल ठीक प्रकार वितरण नहीं कर सकती और वह सारा चोर बाजार में जा रहा है। पश्चिमी बंगाल ऐसा राज्य है जहां विद्युतीकरण सब से कम है। इस कारण मिट्टी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है।

हम से यह वायदा किया गया था कि गांवों में जिनके पास "क" वर्ग के लोगों का जिनके पास भूमि नहीं है मिट्टी का तेल दिया जायेगा। उन्हें थोड़ा तेल मिल भी जाता है परन्तु उनकी क्या स्थिति है जिनके पास "ख", "ग" तक "घ" वर्ग के कार्ड हैं। हर स्थान से यह आवाज उठाई गई कि "हमें रोशनी दो, हमे खाना दो"। यह वस्तुएँ अभी तक देनी बाकी हैं। पश्चिमी बंगाल विधान सभा में 24 मार्च को मंत्री महोदय ने यह सूचना दी कि केन्द्र ने 69,000 टन मिट्टी का तेल देने का वचन दिया था परन्तु केवल 41,000 टन ही दिया गया है। क्या कारण है कि वहां जनता दुःखी है और केन्द्रीय सरकार अपना वचन दिया हुआ तेल भी नहीं दे रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : संभवतया यह याद होगा कि पिछले वर्ष इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं हुई थी।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAR *in the Chair*]

इस सदन में सेना के लोगों की बड़ाई की गई थी जिन्होंने पिछले पाकिस्तान के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाई। मैं चाहता हूं कि सभा यह भी याद रखे कि तेल उद्योग ने इस में कितना कार्य किया। यह सिद्ध हो गया कि तेल की कमी नहीं होने देंगे और युद्ध की तैयारी में इस कारण कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात की प्रशंसा करे। इसका मुख्य श्रेय तो तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम को जाना चाहिये। श्री के० दे० मालवीय ने इसे स्थापित करके एक सराहनीय कार्य किया है।

अब हमारे अंकलेश्वर तेल के कुओं से 6000 टन प्रतिदिन तेल उत्पन्न होता है। देश में अब तक 400 कुएं खोदे गये हैं। यह भी कह दूं कि भाग्य ने भी हमारा साथ दिया है। नूनमाटी तेल शोधक कारखाना स्थापित हो गया है। जिसमें उत्पादन होने लगा। कोयाली तेल शोधक कारखाने की क्षमता 10 लाख टन पहुंच गई है और दो तीन मास बाद यह 20 लाख टन हो जायेगी। श्रीमती रेणुका राय ने हल्दिया का जिक्र किया था। इसके बारे में बातचीत पक्की हो चुकी है, अब केवल उसके सांझीदारों को चुनने का कार्य बाकी रहा है और अगली मई तक उस पर हस्ताक्षर भी हो जायेंगे। साथ ही हम राजस्थान में भी एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं और यहां हम बड़ी तेजी से तेल की खोज कर रहे हैं। फ्रांस की एक कम्पनी इस खोज के कार्य में लगी हुई भी है।

कुछ सदस्यों ने विपणन संस्था की आलोचना की है। मैं यह तो नहीं कहता कि आलोचना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। परन्तु सदन को यह याद रखना चाहिये कि भारतीय तेल कम्पनी ही वितरण नहीं करती। 80 प्रतिशत कार्य तो अन्य गैर-सरकारी कम्पनियां करती है।

सदन को याद होगा कि पिछले वर्ष में हमने विदेशी मुद्रा की कमी के कारण तेल का आयात बन्द कर दिया और अन्य स्थानों से तेल का आयात किया।

[श्री अलगेसन]

यहां के उत्पन्न तेल के दामों के बारे में हम ने 1 फरवरी 1966 से एक नई नीति आरंभ की। इसका संबंध "पोस्टिड प्राईस" से था न कि "डिस्काउंट" से जोकि हमें इस से मिलता है। इसके कारण हमें अपने यहां उत्पन्न तेल के अधिक दाम मिलने लगे।

कुछ भी हो हमनें इस दिशा में कुछ पग उठाये और तेल के क्षेत्र में कुछ प्रगति की। तेल के उत्पादन शोधन और विपणन की दिशा में काफी प्रगति हुई। कीमतों के बारे में हम मध्यस्थ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कच्चे तेल तथा तेल उत्पादों की दरों के बारे में हम कुछ कर सकेंगे। यह इस लिए भी सम्भव है क्योंकि इन वस्तुओं की दरें निश्चित करने में अन्तर्राष्ट्रीय समवायों का कोई प्रभाव नहीं है। इस समय तो हमारे सामने यह कार्यक्रम है कि तेल में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाय। अतः इस बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने काफी बड़ा कार्यक्रम तयार किया है। यदि धन की व्यवस्था हो गयी तो चौथी योजना में 225 करोड़ रुपये तक व्यय करने का विचार है। लगभग 800 कुयें और खोदे जायेंगे। छिद्रण के काम के बारे में तथ्य यह है कि यह बहुत ही कठिन कार्य है। परन्तु ऐसा नहीं कि हम इस दिशा में कुछ कर न सके। इसके लिए हमें केवल इस्पात के ढांचे की आवश्यकता है और फिर हम स्वयं छिद्रण का कार्य अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। अभी तक तो यह काम विदेशी समवाय ही कर रहे हैं। इस कार्य के लिए 20 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है। 50 हजार रुपये दैनिक ही इस कार्य पर खर्च होंगे। छिद्रण का कार्य अमरीकी लोग बहुत अच्छी प्रकार करते हैं।

समस्या यह है कि हम भूमि पर भी स्वतन्त्रता से छिद्रण कार्य नहीं कर सकते। रूस, तेल के लिए छिद्रण खोज तथा उत्पादन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है। तेल की खोज और इसके उत्पादन के लिए हमने बी०ओ०सी से समझौता किया है और एक सांझो कम्पनो बनाई है जिसको आयल इण्डिया लिमिटेड कहते है। आयल इण्डिया लिमिटेड को 9 प्रतिशत शुद्ध लाभ की गारंटी देकर सरकार इस कम्पनी को भारी वित्तोय सहायता दे रही है। 1962, 1963 और 1964 में हम पहले ही ग्यारह करोड़ रूपये की सहायता दे चुके हैं। 1965 में सात करोड़ रूपये की ओर सहायता देने के लिये हमें कहा गया है। यह कहना कि इस कार्य को बिना किसी की सहायता या विदेशी सहयोग के किया जा सकता है, इस समस्या के वास्तविक स्वरूप को सरल समझना है। तटदूर छिद्रण का अनुभव अमरीकियों को है। रूस को इस प्रकार के छिद्रण का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए, इस कठिन कार्य में हमें इच्छा न होते हुए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ी है। यह बात सिद्ध हो गई है कि तट से दूर क्षेत्रों में तेल के बड़े भण्डार हैं। हम इस बारे में बहुत से देशों से बातचीत कर रहे हैं। अन्त में, चाहे जो भी हमारा सहायोगी हो, उसके साथ ऐसी शर्त रखी जायेंगी जिनसे देश के राष्ट्रीय हितों को हानि न हो। इसके साथ ही हम ऐसा आश्वासन नहीं दे सकते कि हम ऐसा बिना किसी सहायता के कर लेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गॅस आयोग का सरकार ऐसा चेयरमैन नियुक्त करने पर विचार कर रही है जो देहरादून में रहे और आयोग की विभिन्न शाखाओं की गतिविधियों को समन्वित करे और यह सुनिश्चित करे कि इसके कार्य के परीणाम अच्छे निकलें। इण्डियन आयल कार्पोरेशन में कुछ परिवर्तन करने और चेयरमैन को तालमेल स्थापित करने की शक्तियां देने का विचार है। वह तीनों विभागों के कार्य के बारे में योजना बनायेगा और सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा। सरकार ने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के साथ बहुत अच्छा और उचित व्यवहार किया है परन्तु फिर भी उन्होंने दूसरों से यह नहीं कहा है कि भारत में विदेशी विनियोजन के लिए अच्छा वातावरण है और नही उन्होंने दूसरों को देश में आकर धन लगाने की सिफारिश की है। यह उनकी गलती है और खेदजनक है।

जब तक हम आयात किए गए कच्चे तेल के स्थान पर, जिस पर हम पिछले पांच वर्षों से लगातार 4000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं, देश में उत्पादन नहीं करेंगे तब तक हम आत्म-निर्भर नहीं हो सकते। देश में तेल की खोज के भरसक प्रयत्न करके हम आयात किए गए तेल के स्थान पर देश में तेल का उत्पादन कर सकते हैं। अपने देश की तीनो तेल कम्पनियों का, जिसके पास पूंजी तथा तकनीकी

जानकारी के बहुत अधिक साधन है, वह कर्तव्य है कि देश में तेल की खोज करने में हमारी सहायता करें परन्तु यह कम्पनियां सरकार से सहयोग करने और देश के अन्दर तेल के नये साधन खोजने में असफल रही है।

जहां तक तीनों तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी का प्रश्न है, यह पता लगा है कि उनका व्यापार बढ़ने पर भी उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी आरम्भ कर दी है, जिसको वे स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्ति कहते हैं, परन्तु तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ भी हो, यह स्वेच्छापूर्वक नहीं हैं। उसके अतिरिक्त, जब एक ओर तो वे छंटनी कर रहे है परन्तु दूसरी ओर भर्ती की जा रही है। सरकार इस प्रश्न पर पूर्णतया विचार करेगी और आशा है कि जो कुछ भी निर्णय लिए जायेंगे, तेल कम्पनियां उनको कार्यान्वित करने में सरकार से सहयोग करेंगी। हमने हाल ही में एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस प्रतिवेदन पर विचार करने का हमें अभी समय नहीं मिला है।

जहां तक हल्के डीजल तेल का सम्बन्ध है, हम इसके वितरण कार्य में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहना सही नहीं है कि सारे हल्के डीजल तेल का प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। सर्वेक्षण समिति के अनुसार केवल 25 प्रतिशत तेल ही कृषि कार्यों के लिये काम में लाया जाता है और शेष अन्य कार्यों के लिये। इसके बावजूद भी हम महाराष्ट्र तथा गुजरात की मांग को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे हैं। यदि यह बता दिया जाये कि कृषि प्रयोजनों के लिये कितने तेल की आवश्यकता है तो सरकार महाराष्ट्र तथा गुजरात की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार है। सरकार फसल के दिनों में इसकी मात्रा में वृद्धि करने के लिये तैयार है।

मिट्टी के तेल के प्रश्न पर विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा अधिकारियों की सलाह से काफी व्योरेवार विचार किया है। हम ने विभिन्न राज्यों के लिए कोटा निर्धारित करने की एक नई नीति अपनाई है। प्रत्येक राज्य को कोटा दिया गया है और हम इस बात के प्रयत्न कर रहे हैं कि कोटा निर्धारित स्थानों पर पहुंचे। वितरण के मामले में चोर-बाजारी का सामना करने के लिए हमने राज्य सरकारों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियां दी है ताकि अन्य बातों के साथ साथ वे मिट्टी के तेल के मूल्य निर्धारित कर सकें और यह देख सकें कि उसका उचित वितरण हो रहा है। हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि इस राज्यवार कोटे को जिलावार कोटे में बांटें। कुछ लोगों की शिकायत है कि कई राज्यों को कोटा ठीक तरह से नहीं मिलता। केरल को मिट्टी का तेल बहुत कम दिया गया है। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि अब राज्यों को कोटा ठीक तरह से मिले और आगे उपभोक्ताओं में इस का वितरण ठीक प्रकार से हो सके।

हमने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि वे इस राज्य-वार कोटे को ज़िला-वार बाँटे और यह सुनिश्चित करें कि सभी ज़िलों को अपना अपना कोटा मिले।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : आप ने अप्रैल के लिये पश्चिमी बंगाल को जो 30,000 किलो लिटर तेल दिया है, वह बहुत ही कम है।

श्री अलगेसन : मैंने यह पहले ही बता दिया है कि हमने ऐसा क्यों किया है हाल ही में हमने पश्चिमी बंगाल का कोटा बढ़ा दिया गया है। अब यह लगभग 30,000 किलो लिटर है।

श्रीमती रेणुका राय : इस के बावजूद भी यह कम है।

श्री अलगेसन : उर्वरक तथा नई मूल्य नीति के बारे में काफी गलतफहमी हो गई है। उर्वरक कृषि उत्पादन बढ़ाने की समूची योजना का मुख्य अंग है। इस समय हम 1 करोड़ टन गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं। इस पर 360 करोड़ रूपये खर्च होते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रकार प्रतिवर्ष इतना रूपया खर्च करते रहेंगे और इस प्रकार खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये दूसरों पर निर्भर रहेंगे। उर्वरक द्वारा ही केवल हम अनाज सम्बन्धी दूसरों पर निर्भरता को कम तथा दूर कर सकते हैं। अतः हमें उर्वरक के प्रश्न पर इस संदर्भ में ध्यान देना चाहिये।

[श्री अलगेसन]

अब तक हमारे पास उर्वरक सम्बन्धी जानकारी नही थी। परन्तु हाल ही में किये गये कुछ समझौतों के अन्तर्गत हमें यूरिया, अमोनिया, नैफ्था का उत्पादन करने तथा गैस साफ करने सम्बन्धी तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई है। इस की सहायता से अब हम उर्वरक उत्पादन के बारे में अपनी प्रक्रिया का विकास कर सकेंगे। देश में उर्वरक के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय दुर्गापुर और कोचीन की परियोजनाओं को अपने साधनों से ही पूरा करने का है। इस से भारतीय तकनीशनों तथा इंजीनियरों को इन दो कारखानों का निर्माण करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और इस से उन लोगों में विश्वास उत्पन्न होगा तथा भविष्य में हम अपनी परियोजनाओं को स्वयं पूरा कर सकेंगे।

यह कहना ठीक नहीं है कि हमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी आज हमें अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य एक कारखाना लगाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में इस समय दो कारखानें हैं एक कानपुर में और दूसरा गोरखपुर में। परन्तु वहां के मुख्य मंत्री चाहते है कि एक कारखाना मिर्ज़ापुर में भी लगाया जाय। मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों की हमसे शिकायत है कि कोरबा उर्वरक परियोजना निर्माण क्यों नही किया जा रहा है। इस बात के बावजूद कि वहां पर लागत बहुत अधिक आयेगी और यह कारखाना अलाभकारी होगा, वे चाहते हैं कि वहां पर एक कारखाना अवश्य स्थापित किया जाय। मैसूर वालों की शिकायत है कि मंगलौर में अभी तक कारखाना स्थापित क्यों नहीं किया गया यद्यपि इसकी मंजूरी छः वर्ष पूर्व दी गई थी। बिहार के मुख्य मंत्री असंतुष्ट हैं कि बरौनी उर्वरक कारखाना स्थापित करने में शीघ्रता नही की जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं श्री मालवीय जी तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा का सुझाव मान कर इस सारे कार्यक्रम को कैसे छोड़ सकता हूं। यह मेरी समझ में नहीं आता। एक ओर तो श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा चाहती है कि इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाय और दूसरी ओर वह यह भी चाहती हैं कि बरौनी उर्वरक कारखाना स्थापित करने में शीघ्रता की जाय। अतः सभी उर्वरक चाहते हैं।

श्री बृजराज सिंह-कोटा (झालावाड़) : राजस्थान के बारे में क्या स्थिति है।

श्री अलगेसन : राजस्थान में एक ही स्थान पर दो कारखानें लगे हुए हैं।

24 लाख टन उर्वरक पर्याप्त नहीं होगा अतः हमें अन्य 30 लाख टन उर्वरक का उत्पादन करने की बात सोचनी चाहिये। श्री वर्मा रूपये की वापसी के बारे में बहुत चिंतित थे। मेरे विचार में उर्वरक उत्पादन के 24 लाख टन के लक्ष्य को पूरा कर लेने के पश्चात हमें प्रति वर्ष लगभग पांच करोड़ रूपये लौटाने पड़ा करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर परियोजना की क्या स्थिति है ?

श्री अलगेसन : कानपुर परियोजना से वर्ष 1969 तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। यह सब से बड़ी परियोजना है। इस से 200,000 मीट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 450,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। यदि हम अपनी उत्पादन क्षमता और 30 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाना चाहते हैं तो कानपुर परियोजना आधार पर इस क्षमता को प्राप्त करने के लिये 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें 240 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें से 80 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के साम्य शेयर होंगे। इस प्रकार हमें प्रतिवर्ष 16 करोड़ रूपये लौटाने पड़ा करेंगे। इसलिये यह रूपये की वापसी का प्रश्न नहीं है बल्कि यह उर्वरक प्राप्त करन का प्रश्न है। यदि हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो चौथी योजना के अन्त तक हमारे पास 35 लाख टन यूरिया होगा जिस से 175 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकेगी।

जहां तक उर्वरक की महंगाई का प्रश्न है, चुंकि इस वस्तु की कमी है इसलिये यह काले बाज़ार में बहुत महंगा बिकता है। चोर बाज़ारी को बन्द करने का केवल एक ही तरीका है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जाये। अन्यथा मूल्य निश्चित करने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : क्या इसके वितरण के ढंग में भी कोई परिवर्तन करने का विचार है?

श्री अलगेसन : कुछ माननीय सदस्यों की धारणा यह है कि कम्पनी को वितरण सम्बन्धी अधिकार दे कर मैंने उस से पक्षपात किया है। ऐसी बात नहीं है।

श्री क० ना० तिवारी : प्रश्न पूछने का मेरा आशय यह था कि चूंकि इस वस्तु की कमी है और यह अधिकांशतः काले बाज़ार में बिकता है। इस लिये मैंने पूछा था कि क्या सरकार वितरण पद्धति में कोई परिवर्तन करना चाहती है जिस से यह वस्तु किसानों तक पहुंच सके?

श्री अलगेसन : हमने वितरण के लिये दो पद्धति बनाई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

केरल में उर्वरक कारखाने का अपना वितरण संगठन है और यह अपना विकास स्वयं कर रहा है। कारखाने में यह भी सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि उर्वरक किसानों को समय पर मिले। देश के अन्य भागों में इस समय जो स्थिति है उसमें यहां काफी सुधार हुआ है। देश के अन्य भागों में बनने वाला उर्वरक केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा इकट्ठा किया जाता है और तत्पश्चात इसका वितरण सहकारी समितियों तथा ऐसी ही एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इस से केन्द्रीय उर्वरक पूल को 43 करोड़ रूपये की बचत हुई है। किसान को रियायत देने की बजाय सरकार उन से मुनाफा ले रही है। अतः यह किसान के लिये लाभकारी नहीं है। इसलिये अब हम वितरण पद्धति को बदलना चाहते हैं। वितरण उत्पादन करने वाले कारखाने स्वयं करे, जिससे वे किसानों के पास जा सकें और उनकी आवश्यकताओं आदि के बारे में उनको बता सके।

जहां तक उत्पादन लागत को कम करने की बात है, इस समय यह लगभग 500 रुपये प्रति टन है। नये एककों में यह लगभग 300 रुपये प्रति टन होगी। इसलिये मेरे विचार में यूरिया 650 रूपये प्रति टन की बजाय लगभग 450 रुपये अथवा अधिकाधिक 500 रुपये प्रति टन पर मिल सकेगा। हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिस में अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो, उर्वरक का मूल्य घटाया जाय और किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध किया जाय।

यह शंका व्यक्त की गई है कि गैर-सरकारी उत्पादक ग़रीब किसानों का शोषण करेंगे। सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये नये कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद हम उर्वरक के मूल्यों पर नियंत्रण रख सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नई व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को उर्वरक बहुत सस्ता मिल सकेगा।

भेषज के क्षेत्र में हमने पर्याप्त प्रगति की है। वर्ष 1948 में हमारे देश में औषधियों का उत्पादन नहीं के बराबर होता था परन्तु अब हम 150 करोड़ रुपये की औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं। चौथी योजना के अन्त तक हम 250 करोड़ रुपये की औषधियां तैयार कर सकेंगे। पांच वर्ष पहले हम 11 करोड़ रूपये की औषधियां बाहर से मंगाते थे परन्तु इस समय केवल 8 करोड़ रूपये की औषधियां मंगाते हैं। हमारे निर्यात में भी वृद्धि हुई है। समूचे रूप से हम ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य किया है। परन्तु कुछ ऐसी फर्में हैं जिन में केवल विदेशी धन लगा हुआ है अथवा 80 से 95 प्रतिशत विदेशी धन लगा हुआ है। हम इन फर्मों में भारतीय पूंजी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक कोचीन तथा गोहाटी तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने का सम्बन्ध है, जब वहां पर पूरा उत्पादन होना आरम्भ हो जायेगा तब इस मामले पर विचार किया जायेगा कि क्या इन का विस्तार किया जा सकता है अथवा नहीं।

कोचीन कारखाने के लिये अधिक भट्टी (फरनेस) का तेल देने के प्रश्न पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

[श्री अलगेसन]

जहां तक कलकत्ता में भवनों के लिये दिये जा रहे किराये का सम्बन्ध है, यह किराया वहां के लोक-कार्य विभाग अथवा सम्पदा विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर दिया जाता है ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनका बहुत ही आभारी हूं ।

श्री रामसहाय पाण्डेय (गुना) : काफी पहले भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कोयले से खाद तैयार करने के बारे में निर्णय किया था । विशेषज्ञों की राय मांगी गई थी और उन्होंने कहा था कि यह खाद महंगा पड़ेगा । हमें खाद की बहुत अधिक आवश्यकता है इसलिये उस पहलू को नजरअन्दाज किया जा सकता है । मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना तथा नाफ्था पर आधारित कारखाना स्थापित किया जाये । मैं इस बारे में सरकार का निर्णय जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक पृथक प्रश्न की सूचना दीजिये ।

श्री अलगेसन : मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा । इस प्रश्न पर मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों से बातचीत हुई थी । मैंने उन्हें बताया था कि कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने पर नाफ्था पर आधारित कारखाने की तुलना में 20 प्रतिशत पूंजी अधिक लगेगी । उन्हें यह भी सूचना दी गई थी कि इस समय जर्मनी में एक प्रयोग किया जा रहा है जिससे शायद कोयले से खाद बनाने की पद्धति लाभप्रद सिद्ध हो जाये । पूरे तथ्यों का पता लगने पर हम इस मामले पर भी विचार करने के लिये तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिये रखूं ?

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्विकृत हुए । / *The cut motions were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई । /*The following Demands in respect of the Ministry of Petrolium and Chemicals were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
81	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय . .	16,80,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,24,42,000
136	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	17,38,38,000

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
67	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . .	23,97,000
68	बहु प्रयोजनी नदी योजनाएं . . .	1,34,37,000
69	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	6,00,01,000
132	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	17,95,24,000
133	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	8,80,20,000

श्री नरसिम्हा रेड्डी (राजमपेट) : हमारे देश में बांधों तथा जलाशयों के निर्माण पर अरबों रुपया खर्च किया गया है। यह उन क्षेत्रों में व्यय हुआ है जहां पहले ही वर्षा से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। इन्हीं क्षेत्रों पर अधिक कृपा-दृष्टि रखी जाती है और कारण यह दिया जाता है कि वहां पर साथ साथ उद्योगों का विकास किया जाना है। इसके विपरीत रायल सीमा जैसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है बिजली का अभाव है। रायलसीमा में गत वर्ष केवल 2 इंच वर्षा हुई थी और वहां पर लोगों की दशा बहुत खराब है। अनाज न होने के कारण भुखमरी फैल रही है। सरकार केवल नारे ही लगाती रही है और अभी तक देहातों में बिजली लगाने के आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं। मैंने आंध्र प्रदेश के बिजली के मुख्य-इंजीनियर को कई पत्र लिखे हैं कि जिन गांवों में कुएं बहुत अधिक है वहां बिजली दी जाये। परन्तु उत्तर यही मिला है कि धन के अभाव के कारण योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकती। अकाल वाले क्षेत्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है परन्तु इन सुखे क्षेत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यदि सरकार हृदय से यह चाहती है कि बिजली दे कर कृषको की सहायता की जाये तो उसे सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिये। अब केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को अनुदान दे रही है। उसे इन अनुदानों का 75 प्रतित भाग अलग रख देना चाहिये और राज्यों से कहना चाहिये कि वे 75 प्रतिशत राशि सुखें क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने पर खर्च करें। यह कार्य तब तक जारी रहना चाहिये जब तक 80 प्रतिशत गांवों में बिजली न पहुंचा दी जाये। रायलसीमा के शुष्क क्षेत्र में जो लोग बिजली प्रयोग में लायें उनसे कुंओं से पम्पों द्वारा पानी निकालनेपर खर्च होने वाली बिजली का आधा शुल्क लिया जाना चाहिये क्यों कि वहां के लोग बहुत ही गरीब हैं और वे पूरा शुल्क अदा नहीं कर सकते हैं।

सरकार को बिजली के खर्च के बारे में वर्तमान नियमों को अधिक उदार बना देना चाहिये। यह बहुत ही अनुचित है कि किसानों से विशेषकर रायलसीमा के किसानों से प्रति हार्सपावर 35 रुपये न्यूनतम शुल्क वसूल किया जा रहा है। उनसे तीन रुपये प्रति हार्सपावर से अधिक शुल्क वसूल नहीं किया जाना चाहिये।

बिजली विभाग में भी भ्रष्टाचार फैल गया है। सुपरवाइजरों तथा उनके नीचे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री नरसिम्हा रेड्डी)

आंध्र प्रदेश के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि राज्य विद्युत बोर्डोंपर कांग्रेसी ही मनोनीत किये जाते है। उनमें विरोधी दलों के कुछ सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

सिंचाई मंत्री को वित्त मंत्रालय से बातचीत करके यह सुनिश्चित करा देना चाहिये कि उन किसानों को जो डीजल पम्पो को काम में लाते हैं डीजल तेल का पर्याप्त कोटा रियायती दरों पर मिल जाये।

रायलसीमा क्षेत्र में कूंओं में ट्यूब गाढ़ कर नीचे से पानी निकाला जा सकता है और कुछ बड़े बड़े किसानों ने ऐसा करके जमीनों की सिंचाई भी की है। ऐसे कूंओं में छेद करने के लिये मैंने एक योजना बनाई है जिसके बारे में मैं मंत्री महोदय से बातचीत करने के लिये तैयार हूं। यदि इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जाये तो रायलसीमा काफी हद तक अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा।

जहां तक सिंचाई आदि परियोजनाओं का सम्बन्ध है राज्य सरकारें केन्द्र के आदेशों का पालन नहीं करती है और वे उन आदेशों की ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं। इस बारे में प्रायः परियोजना का उदाहरण दिया जा सकता है। इस परियोजना पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही कार्य आरम्भ किया गया था। इसी तरह राजमपेट में टोगरूपेट नाम की एक परियोजना का शिलान्यास बहुत पहले किया गया था। पांच वर्ष हो गये है परन्तु वह पत्थर ज्यों का त्यों लगा हुआ है और इससे आगे कोई भी कार्यवाही नही की गई है।

कड़पा तथा चित्तूर जिलों में पापाग्नि पर नदी परियोजना आरम्भ की जा सकती है। इससे एक तालुक के तीन चौथाई भाग और अन्य तालुक के एक-चौथाई भाग में सिंचाई की जा सकती है। मैंने डा० के० एल० राव० को इस बारे में लिखा है और मुझे आशा है कि इसे आरम्भ किया जायेगा। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिये ज्यों लोगों के कहे बिना ही सभी नदियों पर परियोजनाओं की संभावनाओं की जांच करके दो वर्ष में अपना प्रतिवदन दे दें। इस पर तुरन्त अमल किया जाना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सतर्क रहना चाहिये कि इसके आदेशों का पालन किया जाये। यदि राज्य सरकारे केन्द्र के आदेशों की अवहेलना करती है तो यह देश के लिये बहुत ही बुरी बात होगी।

कांग्रेस दल यह अनुभव कर रहा है कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति कम हो रही है। लोक यह समझते है कि मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के मामलों में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। नेता के चुनाव के मामले में, भारत रक्षा नियम हटाने के मामले में, क्षेत्रीय प्रतिबन्ध दूर करने के मामले में अथवा बस्तर के मामले में जांच न्यायालय के विस्तार के मामले में वह विरोध करते हैं। केन्द्रीय अधिकार सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका यह है कि लोक-सभा के लिए उम्मीदवार कांग्रेस का केन्द्रीय संसदीय बोर्ड चुने और यह मामला मुख्य मंत्रियों तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों के हाथों में न छोड़ा जाये। इससे कांग्रेस दल को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार सत्तारूढ दल के हाथों में है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय महत्वपूर्ण मंत्रालय है और यदि इसे राजनैतिक प्रभाव से परे रह कर चलाया गया तो देश को स्थायी लाभ होगा और देश में समृद्धि होगी।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगो के सम्बन्ध में दिम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			रुपये
68	7	उड़ीसा में अपर इरावती हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना को चौथी पंच-वर्षीय योजना में आरंभ करने की वांछनीयता।	100
67	8	दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के कार्यकलापों में तेजी लाने और उन्हें राजधानी में उपेक्षित मस्जिदों की मरम्मत करने के लिये मनाने की आवश्यकता।	100
67	9	दिल्ली में वक्फ़ की सम्पत्ति को जो, अनधिकृत कब्जे में है, वापस लेने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100
67	10	केरल में कुट्टायी सिंचाई परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता	100
67	11	केरल के मलाबार क्षेत्र के लिये तापीयसंयंत्र स्थापित करने कि आवश्यकता	100
67	12	पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाकर केरल में प्रति वर्ष होने वाली बिजली की कटौती की प्रथा समाप्त करने की आवश्यकता।	100
67	13	केरल में विद्युत्जनन को केन्द्रीय क्षेत्र के उद्योग के रूप में आरम्भ करने की आवश्यकता।	100
67	14	केरल में 100 मेगावाट का तापीय संयंत्र लगाने की आवश्यकता	100
67	15	अधिक पन-बिजली बनाने के लिये केरल की सभी नदियों से लाभ उठाने की आवश्यकता।	100
67	16	केरल में बिजली की कमी न होने देने की आवश्यकता	100
67	17	केरल में पश्चिमी तट की नहर बनाने में धीमी प्रगति	100
67	18	केरल में कुट्टीयाडी नदी घाटी परियोजना के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता।	100
67	19	कुट्टीयाडी पन-बिजली परियोजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता	100
67	20	केरल बिजली बोर्ड में अनाचार	100
67	21	केरल में समुद्र से भूमि का कटाव रोकने की आवश्यकता	100

श्री बृजराज सिंह-कोटा (झालावाड) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सिंचाई से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विभागों में तालमेल नहीं है। राजस्थान के सिंचाई विभाग ने कहा है कि चम्बल सिंचाई योजना के अधीन आने वाले कुछ क्षेत्र कृषि योग्य नहीं है। यह क्षेत्र लगभग 2 लाख एकड़ है। अन्य सम्बन्धित विभागों ने इस परामर्ष की ओर ध्यान नहीं दिया है और वहां पर भूमि बांट दी है। इसके परिणामस्वरुप वहां भूमि का कटाव बढ़ गया है। मैंने उस सदन में अपने पहले भाषण में ही भूतपूर्व कोटा राज्य के 'महकमा बंधात' का उल्लेख किया था। उसके द्वारा बनाये गये बान्धों की मरम्मत की जानी चाहिये जिससे कटाव तथा ऊपर की भूमि का बह जाना रोका जा सके।

चम्बल योजना आरम्भ होने से इस समय तक लगभग 18,000 एकड़ भूमि अनुपयोगी हो गई है। वहां छः वर्षों में इतनी अधिक भूमि सेम के कारण बेकार पड़ी है क्योंकि वहां की भूमि

[श्री बृजराज सिंह-कोटा]

ऐसी है कि वहां पानी जमा हो जाता है। जब उन नहरों के रेखांकन पर 6 करोड़ रुपया व्यय होगा और समय भी बहुत लगेगा। समझ में नहीं आता कि शुरु में योजना बनाते समय इन सभी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया।

राजस्थान में योजनायें आरम्भ होने के समय से 23 माध्यम कृषि योजनाओं बनाई गई। उनमें से दो को छोड़ कर जो कि मेरे क्षेत्र में है, सभी पूरी हो गई हैं, उनमें से एक भीम सागय है और दूसरी काली-सिन्ध परियोजना। भीम सागर के निर्माण के विलम्ब से कृषकों को बहुत कठिनाई हो रही है। इसपर लागत भी 18 लाख रुपये से बढ़कर 75 लाख रुपये हो गई है। काली सिन्ध योजना भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई है। मेरा सुझाव यह है कि "कनवास" क्षेत्र को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाये। उच्चतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव स आम लोगों को कठिनाई हो रही है। ऐसा वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिये ।

मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। 1960 तक राजस्थान के ग्रामों में विद्युत नहीं थी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राजस्थान को कम से कम 2.5 करोड़ रुपय दिये जायें ताकि राज्य विद्युत बोर्ड भावी विद्युतीकरण कार्य-क्रम शीघ्रता से क्रियान्वित कर सके। गांधीसागर बान्ध तथा अन्य बान्धों से जल के प्रयोग के मामले में अधिक तालमेल होना चाहिय। राजस्थान के जैसलमेर, बारमेर, पश्चिमी जोधपुर तथा बीकानेर के मरुस्थलीय क्षेत्रों में नलकूप मैंने ८खे है। खेद की बात है कि शायद राजनैतिक झगड़ों के कारण उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। उनका तुरन्त प्रयोग किया जाना चाहिये।

श्रीमती विमला देवी (एलुरू) : पिछले वर्ष सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए, माननीय मंत्री ने बताया था कि 30 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये अतिरिक्त जल की क्षमता की पूर्ति हो जायेगी। परन्तु 10 लाख एकड़ की कमी है। विद्युत के सम्बन्ध में 1 करोड़ 10 लाख किलोवाट का लक्ष्य था। 10 लाख किलोवाट विद्युत की भी कमी है। यद्यपि सरकार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकी है फिर भी अच्छी सफलता रही है। इसके लिय मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

आजकल देश को खाद्यान्न की कमी के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सारे देश में, विशेषतया, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और केरल में खाद्यान्न की समस्या के बारे में आन्दोलन चल रहे है। सरकार समस्या को सुलझाने के बजाय लोगों पर गोली चलवा रही है। मैं खाद्यान्न के आयात के विपक्ष में नहीं हूं परन्तु सरकार जिस प्रकार की रियायतें अमरीकी साम्राज्यवादियों को दे रही है मैं उनका विरोध करती हूं क्योंकि वे रियायते देश के हित में नहीं हैं।

सरकार को चाहिये कि खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिय सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करे। इससे हम न केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते है बल्कि पिछड़े देशों को भी कुछ सहायता कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के 18 वर्षों बाद भी देश मे पर्याप्त अन्न नहीं पैदा हो रहा है। यह इसलिये है कि सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत के विकास की उपेक्षा की है।

खेती के लिये प्रथम आवश्यकता सिंचाई की होती है। जल निकास, उर्वरकों तथा वैज्ञानिक ढंगों के अपनाने की बारी इसके बाद में ही आती है। मेरे जिलें में सरकार उर्वरकों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहां सरकार उर्वरकों की मांग की पूर्ति नही कर सकती है। इस वर्ष एक एकड़ भूमि के लिये 1 किलोग्राम अमोनिया दी जा रहा है।

पश्चिमी गोदावरी जिले में कृषकों को जल की आवश्यकता है। आज लाखों लोगों को सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है। 1964 में खाद्यान्न की अच्छी पैदावार हुई थी। 1965

में अनावृष्टि के कारण 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन अन्न कम पैदा हुआ। अतः सिंचाई की उचित व्यवस्था किये जाने की बड़ी महत्वता है।

गोदावरी बांध 120 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इससे पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों को जल मिलता है। परन्तु अब यह बहुत पुराना हो गया है। लोग बार बार आन्दोलन उठा रहे हैं कि इस बांध की जगह अब नया बांध बनवाया जाय। केन्द्रीय सरकार ने बांध की अवस्था के अध्ययन के लिये मित्रा समिति नियुक्त की थी। मित्रा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि इस बांध की मियाद अब पूरी हो चुकी है और वह कभी भी बहाव में टूट सकता है। राज्य सरकार कहती है कि उसके पास धन नहीं है। जिससे कि नया बांध बनवाया जा सके। यदि केन्द्रीय सरकार 17 करोड़ रुपया इस परियोजना पर व्यय कर दे तो बहुत अच्छा होगा।

मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में तथा और भी कहीं जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, केन्द्रीय सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिये। नागार्जुनसागर जैसी परियोजना के पूरे होने पर 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। खाद्य समस्या को देखते हुये इसे शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये।

सिंचाई क्षमता की व्यवस्था की नहीं बल्कि उसका पूरा-पूरा उपयोग भी किया जाना चाहिये। नहरों की खुदाई भी बड़ी आवश्यक है।

बाढ़ नियंत्रण तथा जल निस्सारन की भी बड़ी महत्वता है। बाढ़ से फसलें बह जाती हैं। पंजाब में जल-लग्नता के कारण फ़सलों पर बरा असर पड़ता है। गोदावरी और डेलटा ज़िलों में जल-निस्सारण का भारी जमाव है। बाढ़-नियंत्रण के लिये अनुमोलंका, थम्मीले तथा बुदामेरु परियोजनाओं को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी यही समस्या है। जल-निस्सारण की समस्या बड़ी जरूरी हो गई है। यदि इस पर ध्यान दिया जाये तो लाखों टन अनाज बर्बाद होने से बच जायेगा। इस कार्य को यदि राज्य सरकारें न कर सकें तो केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये।

वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण देरी हो रही है। सरकार को चाहिये देश को आत्म-निर्भर बनाने की पूरी कोशिश करे। आवश्यक मशीनरी का उत्पादन देश में ही किया जाये।

उद्योगों तथा कृषि दोनों के ही लिये विद्युत शक्ति का बड़ा महत्व है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति 60 से 70 यूनिट विद्युत का उपयोग करता है परन्तु विदेशों में 3,000 से 6,000 युनिट का उपयोग होता है। आज रूस एक शक्तिशाली देश है। उस की खुशहाली का रहस्य विद्युत शक्ति है। विद्युत के सम्बन्ध में 1920 में रूस और भारत की समान स्थिति थी। आज संसार में रूस का दूसरा स्थान है। और कुछ ही समय में अमरीका से आगे निकलने की आशा है।

देश में कोयला, जल, अणु शक्ति इत्यादि की कमी नहीं है फिर भी सरकार ने औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्रों में केरल में 80 प्रतिशत और आंध्र में 60 प्रतिशत कटौती की है।

हम अभी तक जल-विद्युत के विकास पर अधिक ध्यान देते रहे हैं। परन्तु इस वर्ष अनावृष्टि के कारण यह सिद्ध हो चुका है कि जल-विद्युत के साथ-साथ ताप बिजली का भी विकास किया जाना चाहिये। केरल में विद्युत की कटौती के कारण उर्वरक कारखाने को 2.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है। हजारों लघु-उद्योगों को क्षति पहुंची है। कृषि के लिये विद्युत की सप्लाई दिन में केवल 2 अथवा 3 घंटे के लिये होती है। परन्तु बिजली बोर्ड यही कहता है कि कृषि के लिये विद्युत में कोई कटौती नहीं की गई है।

देश में जितनी बिजली उत्पन्न की जाती है उसमें से 90 प्रतिशत बिजली उद्योगों तथा कृषि में खर्च होती है। कृषि के लिये भी पर्याप्त बिजली दी जानी चाहिये।

[श्रीमती विमला देवी]

यदि ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत शक्ति दी जाये तो वहां की काया-पलट हो जाये। कुटीर-उद्योग एकदम प्रगति कर जायेंगे। बिजली पम्प सेट से पानी निकलने का कार्य बड़ी आसानी और शीघ्रता से किया जा सकता है। डीज़ल इन्जिन से बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि यह प्राय: खराब होता रहता है। डीज़ील पम्प सेट महंगे भी रहते हैं।

सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाने पर फसलें बहुत अच्छी होंगी। मैंने माननीय मंत्री को बताया है कि 30 से 40 एकड़ भूमि दो फसलों के लिये सींची जा सकती है। देश में ऐसे बहुत से भाग ह जहां केवल कुंओं से ही सिंचाई की जा सकती है। देश के ऐसे भागों को विद्युत द्वारा ही सींचा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि ऐसे क्षेत्रों को काफी विद्युत दी जाये।

देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत के विकास के बारे में बड़ी असमानता है। जिन राज्यों में अधिक उद्योग है उन को अधिक विद्युत दी जाती है। अत: मद्रास और महाराष्ट्र को अधिक बिजली सप्लाई की जाती है। आंध्र प्रदेश को सबे से कम बिजली दी जाती है। आंध्र प्रदेश में कोयला, पानी तथा खनिज जो उद्योगों के लिये आवश्यक है कमी नही है फिर भी इस राज्य का औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि दूसरी तथा तिसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नैलोर तथा तुंगभद्रा को छोड़ कर और कोई परियोजना नही बनी। हमें श्रीसेलम परियोजना की बड़ी प्रतीक्षा थी। इस परियोजना पर किसी न किसी कारण से कार्य नही हो सका है।

केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये प्रत्येक राज्य में नीवेली जैसी परियोजना बनाये।

चौथी योजना के दौरान ताप विद्युत तथा जल-विद्युत दोनों का विकास किया जाना चाहिये। विद्युत के उचित वितरण पर जोर दिया जाना चाहिये। देश में जहां भी विद्युत शक्ति उपलब्ध नही है। राज्यों की माली सीमा के अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। राज्यों को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिय परन्तु केन्द्रीय सरकार को भी प्रत्येक राज्य में बड़ी परियोजनाओं की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं चाहती हूं कि पारेषणलाइनों पर सरकार अधिक व्यय करे। यदि किसी एक स्थान पर अधिक विद्युत मिलती है तो सारे उद्योगपति उसी स्थान के आस-पास अपने उद्योग स्थापित कर देते है। प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण हे यह ठीक नही है। पर्याप्त लाइने होने पर ऐसे क्षेत्रों से जहां अधिक है कमी वाले क्षेत्रों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। लाइनों की कमी के कारण मैसूर से, जहां अधिक बिजली उपलब्ध है, केरल और आंध्र में बिजली नहीं ले जाई जा सकती। इसी प्रकार गुजरात से राजस्थान और पंजाब में बिजली ले जाई जा सकती थी यदि लाइनों का निर्माण हो गया होता। सरकार को रुपया कम कर के अधिक से अधिक पारेषण लाइने बनानी चाहिये। विदेशों में 50 प्रतिशत व्यय बिजली बनाने और 50 प्रतिशत व्यय पारेषण लाइनों पर होता है। मैं चाहती हूं कि हमारे देश में भी ऐसी ही व्यवस्था हो जाये। अत: पारेषण लाइनों पर अधिक व्यय किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 12 अप्रैल, 1966/ 22 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the April 12, 1966/Chaitra 22, 1888 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि1—53 लोक सभा/66—28-8-67—600.